



कांकेर में सीएफ जवान ने बनाई मां दुर्गा की प्रतिमा, हुनर को अफसर भी कर रहे सलाम



**कांकेर।** रविवार से दुर्गा पूजा का आरंभ हो रहा है। पूरे बस्तर में अभी से भक्तिमय माहौल बन गया है। दुर्गा पूजा मंडली नवरात्र के आयोजन को भव्य रुप देने में जुटी है। भीरगांव में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल यानी सीएफ की 22 बटालियन का मुख्यालय भी है। यहां भी इस बार भव्य रुप से मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। सीएफ मुख्यालय में जो दुर्गा पूजा होगी उसकी खासियत है कि यहां पर प्रतिमा खरीदकर नहीं लाई जाएगी, बल्कि यहां पर प्रतिमा का निर्माण खुद सीएएफ जवान रूपधर चौहान कर रहे हैं। रूपधर चौहान कहते हैं कि बचपन में ही उनको प्रतिमा निर्माण करने का शौक चढ़ा जो आज तक

बना हुआ है। रूपधर बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो अपने भाई के साथ मिलकर इस काम को किया करते थे। उनका ये शौक धीरे-धीरे बढ़ता गया और वो एक साथ कई प्रतिमाओं के निर्माण भी करने लगे।

रूपधर बताते हैं कि सीएएफ में आने के बाद उनको उनके अधिकारी ने बताया कि हम दुर्गा पूजा करने वाले हैं। इसपर उन्होंने अधिकारी को बताया कि वो मूर्ति का निर्माण करना जानते हैं। अगर वो कहें तो इस बार वो मूर्ति खुद अपने हाथों से बनाकर यहां स्थापित करेंगे। अफसरों की रजामंदी के बाद वो पिछले कई सालों से मां दुर्गा की प्रतिमा और गणपति की स्थापना कर रहे हैं।

कोरबा नगर निगम के काम पर सवाल, सड़क के शेड पर फॉल्स सीलिंग लगाने का विरोध

**कोरबा।** कोरबा नगर निगम के सीएसईबी चौक पर निर्मित शेड में इन दिनों फॉल्स सीलिंग का काम चल रहा है। महानगरों के तर्ज पर ट्रैफिक सिग्नल पर ठहरने वाले लोगों को धूप और बारिश से बचने के लिए बड़े शेड का निर्माण किया गया है। अब इस शेड के भीतर ऊंचाई पर फाल्स सीलिंग लगाया जा रहा है, निगम का यह कार्य स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों के गले नहीं उतर रहा है। फॉल्स सीलिंग की उपयोगिता पर सवाल उठ रहे हैं। इस कार्य की कुल लागत लगभग 35 लाख रुपए है।

विपक्ष के लोग सवाल उठा रहे हैं कि ज़रूरत जमीन पर सड़क के मरम्मत की है, लेकिन निगम आसमान में फॉल्स सीलिंग करवा रही है। यह कार्य लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। सीएसईबी चौक में एक तरफ के रास्ते को इस कार्य के लिए पिछले लगभग एक हफ्ते से पूरी तरह बलॉक कर दिया गया है, इस वजह से आम लोग दूसरी दिशा से घूम कर शहर में प्रवेश कर रहे हैं और बाहर निकालने के लिए भी दूसरी दिशा की सड़क का इस्तेमाल कर रहे हैं।

उपनगरीय क्षेत्र में सड़कों की स्थिति बहाल इस कार्य पर अधिक सवाल उठने का प्रमुख कारण शहर की सड़कें हैं। मुख्य शहर से लेकर उपनगर क्षेत्र की अंदरूनी सड़कें बेहद बर्दाश हैं जिनके लिए कई आंदोलन हुए। विपक्ष के साथ स्थानीय लोगों



ने भी जिम्मेदारों से शिकायत की है। हाल ही में स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री ने भी सड़कों की बर्दाहली पर सज़ान लिया और इसे ठीक करने की बात कही थी। लखन लाल देवांगन ने स्पष्ट किया था कि मानसून सीजन और बारिश का दौर थमने के बाद शहर के हिस्सों में सड़कों के डामरीकरण और विशेष मरम्मत का कार्य युद्धस्तर पर शुरू कर दिया जाएगा। उनका दावा है कि कागजी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।

शहर के प्रमुख मार्गों और अंदरूनी कॉलोनियों की सड़कों को दुरुस्त करने के लिए लगभग साढ़े 27 करोड़ रुपये की लागत से टेंडर जारी किए गए हैं। हालांकि बारिश थमने के बाद निगम ने प्रमुख चौक चौराहों पर गड्ढों को भरने का काम ज़रूर किया है, लेकिन यह अभी लोगों के लिए

मुसीबत बनी हुई है इस मार्ग से अब धूल का गुबार उड़ रहा है।

फॉल्स सीलिंग का विरोध कर रहे नेता प्रतिपक्ष कृपाराम साहू का कहना है कि नगर पालिक निगम कोरबा में जिन कार्यों में कमीशन अधिक मिलता है और उपयोगिता कम रहती है। वो कार्य सबसे पहले होते सीएसईबी चौक पर दोनों तरफ शेड का निर्माण किया गया है, जिसका मकसद गर्मी और मानसून के सीजन में लोगों को धूप और बारिश से बचाना है। ट्रैफिक सिग्नल पर जब लोग रुकें, तो उन्हें धूप और बारिश से बचाया जा सके इस सोच के साथ शेड का निर्माण किया गया था। शेड निर्माण तक तो बात ठीक थी, लेकिन अब, जब शेड के भीतर फॉल्स सीलिंग लगाई जा रही है, तब इसका विरोध शुरू हो गया है, इसकी उपयोगिता पर सवाल खड़े हुए हैं।

गोबरी नदी में माइनिंग अधिकारी पहुंचे तो खाली मिले ट्रक, ड्राइवर फरार



**कोरिया।** जिले के पटना तहसील अंतर्गत डुमरिया क्षेत्र की गोबरी नदी में कथित अवैध रेत उत्खनन और परिवहन का मामला सामने आया है। ग्रामीणों के मुताबिक क्षेत्र में सुबह से ही नदियों से रेत निकालने और उसे बड़े बड़े ट्रकों के जरिए परिवहन करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। लंबे समय से गोबरी नदी से रेत निकाले जाने की शिकायतें सामने आती रही है। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने से रेत तस्करों के हौसले बुलंद है। बारिश थमते ही नदी से रेत तस्करी का काम शुरू हो गया है। स्थानीय ग्रामीण का आरोप है कि तड़के सुबह 5 बजे से ही गोबरी नदी से रेत खनन चालू हो जाता है। गोबरी नदी किनारे मौके पर ट्रैक्टर, ट्रक और कई मजदूर रेत को गाड़ियों में भरते नजर आए। गोबरी नदी से

तड़के सुबह 5 बजे से ही रेत की लोडिंग शुरू हो जाती है। सुबह होते होते रेत से लदे वाहनों की आवाजाही भी बढ़ने लगती है। रेत से लदी गाड़ियां तेज गति से दौड़े लगती है- अनिल कुमार, स्थानीय ग्रामीण गोबरी नदी के किनारे रेत परिवहन में लगे कुछ वाहनों में नंबर प्लेट भी नहीं मिले। वहीं कई वाहनों में लगी नंबर प्लेट में नंबर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे थे।

नदियों से रेत का उत्खनन निर्धारित नियमों और पर्यावरणीय शर्तों के अनुरूप होना आवश्यक है। यदि किसी क्षेत्र में अनुमति के बिना या निर्धारित सीमा से अधिक उत्खनन किया जाता है, तो इससे नदी के प्राकृतिक स्वरूप, जल प्रवाह और आसपास के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका रहती है।

दुर्ग में सीएम के कार्यक्रम में बच्चों को बुलाने पर सियासत

**दुर्ग भिलाई।** मुख्यमंत्री साय के कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को शामिल किए जाने का मामला अब राजनीतिक मुद्दा बन गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकारी कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए छोटे-छोटे स्कूली बच्चों का इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस नेताओं ने इसे लेकर विरोध प्रदर्शन किया और जिला शिक्षा अधिकारी जगजीत सिंह धीर को ज्ञापन सौंपते हुए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस जिला अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल का आरोप है कि कार्यक्रम में शासकीय और निजी स्कूलों के बच्चों को बुलाया गया था, लेकिन उन्हें बुलाने के लिए कोई स्पष्ट आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया। कांग्रेस का कहना है कि बच्चे सुबह करीब 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहे। तेज गर्मी के बीच बच्चों के लिए पर्याप्त पानी और भोजन की व्यवस्था नहीं होने का भी आरोप लगाया गया। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक, कई बच्चे घर से लाया हुआ टिफिन खाने को मजबूर हुए। कांग्रेस ने कहा कि छोटे बच्चों को घंटों कार्यक्रम में बैठाए रखना बेहद गंभीर मामला है और इसकी शिकायत कलेक्टर से भी की जाएगी। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी जगजीत सिंह धीर ने कांग्रेस के ज्ञापन की पुष्टि करते हुए कहा कि रंगोली कार्यक्रम में निजी स्कूलों के बच्चे शामिल होने आए थे। उन्होंने बताया कि प्रशासन की तैयारी बैठक में कार्यक्रम को लेकर निर्देश दिए गए थे।

पानी मांग रहे ग्रामीणों पर कार्रवाई से बवाल

पुलिस ने माता-पिता को उठाया तो सड़क पर उतरे बच्चे, थाने के सामने कर रहे प्रदर्शन



बालोद। पीने के पानी की मांग को लेकर दल्लीराजहरा –महामाया मार्ग पर बीते तीन दिनों से चक्काजाम और आमरण अनशन कर रहे ग्रामीणों को पुलिस ने आज सुबह उठा लिया। 102 पुरुषों को ओपन थिएटर दल्ली राजहरा और 30 से 40 महिलाओं को आईटीआई में पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है। माता-पिता को पुलिस ने उठाया तो 40 से अधिक बच्चे पैदल 10 किमी चलकर थाने

पहुंचे। पुलिस ने गेट के पहले ही रोका तो बच्चे सड़क पर ही बैठ गए हैं और अपने माता-पिता को छोड़ने एवं बोइरडीही गांव से पानी देने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि आड़ेझर गांव के हजारों ग्रामीण बोइरडीही जलाशय से पीने का पानी देने की मांग को लेकर गुरुवार से सड़क पर बैठे थे। इन्हें से 9 ग्रामीण आमरण अनशन भी कर रहे थे। प्रशासन ने तीन दिनों तक



समझाने का प्रयास किया, लेकिन कोशिश नाकाम होने के बाद पुलिस ने आज कार्रवाई की है। ग्रामीणों के चक्काजाम और आमरण अनशन पर बैठने से महामाया, दुलकी, कलक्टर माईस से कच्चा लोहा लाने वाली हजारों गाड़ियों का परिचालन प्रभावित हो रहा था। पुलिस के बलपूर्वक उठाने से गांव में आक्रोश का माहौल है। सूत्रों के अनुसार, पुलिस कार्रवाई के विरोध में पूरा गांव इकट्ठा होकर गिरफ्तारी दे सकता है।

रामानुजगंज वन वाटिका से इको टूरिज्म हब, डेढ़ करोड़ की लागत से डेवलपमेंट वर्क



**बलरामपुर।** रामानुजगंज वन वाटिका को इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने शुक्रवार को करीब डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से होने वाले निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया। इस दौरान डीएफओ डॉ आलोक वाजपेयी, एसडीएम आनंद नेताम, रेंजर डॉ दिलरूबा, तहसीलदार सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि अधिकारी कर्मचारी सहित आम लोग मौजूद रहे। बलरामपुर जिले के डीएफओ आलोक वाजपेयी ने बताया कि रामानुजगंज में प्रकृति के बीच बने जंगलो से घिरे हुए मनोरम प्राकृतिक पर्यटन स्थल वन वाटिका के लिए विकास की सौगात

मिली है। इस वन वाटिका में अब बच्चों युवाओं और बुजुर्गों के लिए बहुत कुछ विकसित किया जाएगा। वन वाटिका में बैडमिंटन कोर्ट, चिल्ड्रेंस प्ले एरिया बनेगा, ओपन ज़ीम का भी निर्माण होगा। इसके अलावा वुडेन ब्रिज भी बनाया जाएगा जो व्यू प्वाइंट की तरह काम करेगा। इसके अतिरिक्त उद्यान का भी विकास किया जाएगा। डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से विकास सहित अन्य कार्य होंगे, जिसका भूमिपूजन किया गया, वन विभाग के जिला अधिकारी का कहना है कि अगले तीन महीने में यह सभी निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

होटल में युवती की संदिग्ध मौत मामले में प्रेमी गिरफ्तार

**धमतरी।** होटल में 22 वर्षीय युवती की मौत के मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए। कवर्था से धमतरी आई युवती होटल के कमरे में मृत मिली थी। अब इस मामले में पुलिस ने उसके कथित प्रेमी टिकेश्वर उर्फ टिंकू साहू को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, युवती को शादी का भरोसा देने, बाद में शादी से इनकार करने और प्रताड़ित करने के आरोपों की जांच के दौरान आरोपी की सिलसिला से जुड़े साक्ष्य मिले हैं। मृतका पिंकी मानिकपुरी (22 वर्ष), निवासी कवर्था, जिला कबीरधाम का है। पुलिस के अनुसार, युवती और टिकेश्वर उर्फ टिंकू साहू के बीच प्रेम संबंध थे। आरोप है कि युवक ने उससे शादी करने का भरोसा दिया था। इसी बीच युवती को आरोपी के दूसरी लड़कियों से संबंध होने की जानकारी मिली। इस बात की सच्चाई जानने और शादी को लेकर बातचीत करने के लिए युवती 24 सितंबर को धमतरी पहुंची थी। रुद्री रोड स्थित होटल सीजी-05 के कमरा नंबर 106 में ठहरी थी। धमतरी एसपी डीसी पटेल ने बताया कि 25 सितंबर की शाम आरोपी युवती से मिलने होटल पहुंचा।

अवैध शराब पकड़ने पहुंची पुलिस टीम से अभद्रता

**डोंगरगढ़।** शहर में अवैध शराब की बिक्री की सूचना पर कार्रवाई करने पहुंची पुलिस टीम के साथ विवाद और मारपीट का मामला सामने आया है। शुक्रवार रात मोचीपारा के रविदास नगर में हुई इस घटना में कुछ युवक और महिलाएं शामिल बताए जा रहे हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और घटना में शामिल लोगों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार डोंगरगढ़ थाना पुलिस को शुक्रवार रात मोचीपारा स्थित रविदास नगर में अवैध शराब बेचे जाने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद डोंगरगढ़ पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी। यहां अवैध शराब को लेकर कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों के साथ पुलिस जवानों का विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि विवाद बढ़ने के बाद मौके पर मौजूद कुछ युवक और महिलाएं पुलिसकर्मियों से उलझ गए। इस दौरान झुमाझटकी और मारपीट किए जाने का आरोप है।

फांसी की सजा पाने वाले तीन आरोपियों की शिफ्टिंग

**सूरजपुर।** सूरजपुर में चर्चित दोहरे हत्याकांड मामले में फांसी की सजा पाने वाले दोषियों को अलग-अलग जेलों से शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जेल प्रशासन ने तीनों आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच केंद्रीय जेल रायपुर भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक, 8 अक्टूबर को दोहरे हत्याकांड मामले में सजा सुनाए जाने के बाद जेल प्रशासन ने दोषियों की शिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू की। मामले के तीनों आरोपी अलग-अलग जेलों में बंद थे।इस मामले में आरोपी कुलदीप साहू अंबिकापुर जेल में, फूल सिंह उर्फ रिकू सूरजपुर जिला जेल में और चंद्रकांत चौधरी कोरिया जेल में निरुद्ध था। अदालत के फैसले के बाद अब दोषियों को रायपुर केंद्रीय जेल भेजा गया। वहीं उम्रकैद की सजा पाने वाले आरोपी आर्यन विश्वकर्मा को अंबिकापुर जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। यह मामला 13 अक्टूबर 2024 को तत्कालीन प्रधान आरक्षक की पत्नी और उनकी 11 वर्षीय बेटी की हत्या से जुड़ा है। इस दोहरे हत्याकांड ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी।

नगर पालिका के बकायादारों पर नकेल कसने की तैयारी

**बीजापुर।** नपा बीजापुर के बकायादारों पर अब प्रशासन की नकेल कसने की तैयारी है। नगर में 50 से अधिक लोगों पर नपा का करीब 75 लाख रुपये बकाया है। संबंधित बकायादार पिछले करीब दो सालों से नपा द्वारा जारी नोटिसों की अनदेखी कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, कुछ बकायादारों पर एक लाख रुपये से अधिक की राशि बकाया है। लंबे समय से बकाया राशि जमा नहीं होने और नोटिसों की अनदेखी के बाद अब नगर पालिका ने मामला जिला दंडाधिकारी के समक्ष पहुंचा दिया है। अब इस मामले में जिला प्रशासन की ओर से आगे क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। यदि प्रशासन सख्ती बरतता है, तो लंबे समय से बकाया राशि जमा नहीं करने वालों पर कार्रवाई हो सकती है। बीजापुर के सीएमओ बंशीलाल नुरेटी ने कहा कि इसमें 2019-20 से वार्षिक निविदा वाले 16 लोग हैं। इनका 18 लाख रुपया है, सन 2021 से पेंडिंग 14 दुकानों की उच्चतम बोली की राशि लगभग 40 लाख रुपया और दुकान किराया 26 लोगों से 18 लाख सरकारी राशि है।

आयुष्मान कार्ड से कैशलेस इलाज का झांसा देकर की वसूली

**धमतरी।** धमतरी में एक निजी अस्पताल पर गंभीर आरोप लगा है। आरोप है कि मरीज को आयुष्मान कार्ड से कैशलेस से इलाज का झांसा देकर डबल वसूली किया गया है। पीड़ित मरीज ने इसकी शिकायत कलेक्टर कार्यालय में की है। जानकारी के मुताबिक, सविल इंजीनियर हरिश्चंद्र देवांगन अपनी टूटी हड्डी का इलाज कराने शिवनंदा हॉस्पिटल पहुंचे थे। मरीज का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने पहले तो बड़ा भरोसा दिया कि सारा इलाज आयुष्मान कार्ड से कैशलेस हो जाएगा और एक रुपया भी नहीं लगेगा, लेकिन इलाज शुरू होते ही आयुष्मान कार्ड से 66 हजार रुपये काट लिए गए और फिर अलग-अलग बहाने बनाकर कभी दवा के नाम पर कभी जांच के नाम पर 60 हजार नगद पैसे भी ऐंट लिए गए। मरीज ने बताया पूरा इलाज आयुष्मान से होगा फिर भी मेरे कार्ड से 66 हजार काट लिए और ऊपर से नागद भी ले लिया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये पहली बार नहीं है। सूत्र बताते हैं कि विवादों से इस अस्पताल का पुराना नाता है।

दंतेवाड़ा में जैविक खेती और स्थानीय उत्पादों से जुड़े ‘दण्डक ब्रांड’ का शुभारंभ

**दंतेवाड़ा।** बस्तर अब ब्रांड बना रहा है। खासकर दंतेवाड़ा जिले की पहचान जैविक खेती और स्थानीय उपज के नाम से जानी जा रही है। इसी कड़ी में एक और कदम उठाते हुए ‘दण्डक ब्रांड’ दुकान का शुभारंभ किया गया है। इस पहल का उद्देश्य जिले में उत्पादित जैविक एवं स्थानीय कृषि उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराना और ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ‘बिहान’ के अंतर्गत मां दंतेश्वरी महिला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (एफपीओ) की ये दुकान है। जहां ‘दण्डक ब्रांड’ के विभिन्न उत्पादों का लोकार्पण किया गया। इनमें नीमफूल, एचएमटी, लालचुड़ी और बासमती चावल के साथ अमचूर, इमली, महुआ, कोदो, कुटकी और रागी जैसे स्थानीय उत्पाद शामिल हैं। इन उत्पादों का मूल्य संवर्धन कर ब्रांडिंग और



आकर्षक पैकेजिंग के साथ बाजार में बिक्री के लिए तैयार किया गया है। इससे स्थानीय उपज को बेहतर कीमत दिलाने, उत्पादों की गुणवत्ता और पहचान को मजबूत करने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की संभावनाएं बढ़ेंगी। ‘दण्डक ब्रांड’ दुकान का शुभारंभ विधायक चैतराम अटामी, जिला अध्यक्ष नंदलाल मुड़ामी, जनपद पंचायत ने किया। कार्यक्रम के दौरान विधायक चैतराम अटामी ने इस पहल की सराहना करते हुए महिला स्व-सहायता समूहों को प्रोत्साहित

एवं प्रोत्साहन दिया। इस पहल से दंतेवाड़ा के स्थानीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने की उम्मीद जताई गई। मां दंतेश्वरी महिला एफपीओ की यह पहल जिले के लगभग 60 उत्पादक समूहों से जुड़ी 2,500 महिला सदस्यों के लिए आजीविका का महत्वपूर्ण माध्यम बन सकती है। इन समूहों की महिलाओं द्वारा तैयार किए जाने वाले स्थानीय एवं जैविक उत्पादों का मूल्य संवर्धन कर ‘दण्डक ब्रांड’ के अंतर्गत बाजार तक पहुंचाने का प्रयास

किया जाएगा। इससे महिलाओं को अपने उत्पादों की बेहतर मार्केटिंग का अवसर मिलेगा। साथ ही स्थानीय कृषि उपज और वनोपज को व्यावसायिक पहचान मिलने से ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने की संभावनाएं भी मजबूत होंगी। यह पहल महिला सशक्तीकरण के साथ-साथ स्थानीय संसाधनों पर आधारित रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कार्यक्रम में उप संचालक पंचायत तरुण देशमुख, एओ प्रमोद दुर्गम, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत प्रांजल प्राणपति, डीपीएम एनआरएलएम नितेश कुमार देवांगन, एफपीओ के सीईओ अभिजीत सरकार, बिहान की टीम, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्य तथा विभिन्न स्व-सहायता समूहों की महिलाएं उपस्थित रहीं।

आदिवासी कल्चर, संस्कृति और रहन सहन पर बनी ओडिया फिल्म मालीपुट मेलोडीज बस्तर में रिलीज

**बस्तर।** बस्तर से लगे पड़ोसी राज्य ओडिशा के कोरापुट में स्थानीय आदिवासियों की भाषा बोली और कल्चर पर बनी एक फिल्म बीते दिनों ओडिशा के अलग-अलग जिलों के सिनेमा थियेटर में रिलीज हुई है। कोरापुट और बस्तर का कल्चर एक दूसरे से जुड़े होने की वजह से शुक्रवार को जगदलपुर शहर में भी इस फिल्म को रिलीज किया गया है। इस फिल्म का नाम मालीपुट मेलोडीज है। फिल्म को रिलीज कर फिल्म निर्माता और कलाकारों ने बस्तर जिले में प्रेस वार्ता करके फिल्म के उद्देश्य और कल्चर की जानकारी दी है। फिल्म निर्माता विशाल पटनायक ने बताया कि ओडिशा के कोरापुट में बोले जाने वाली ओडिया लैंग्वेज में एक फिल्म का निर्माण कराया गया है। यह फिल्म क्षेत्र के निवासियों के रहन-सहन, उनकी भाषा बोली और कल्चर से जुड़ी है। फिल्म के माध्यम से संस्कृति को नेचुरल तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है। कोरापुट और बस्तर में शादी की



परंपरा एक जैसी है। संस्कृति भी एक जैसी ही है। कई बार कोरापुट से आकर बस्तर के शादी में शिरकत करने का मौका मिला, जिससे यह पता लगा कि बस्तर और कोरापुट आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। इस वजह से यहां भी फिल्म रिलीज की गई- विशाल पटनायक, फिल्म निर्माता फिल्म के संगीतकार तोंप नंदा बताया कि हमेशा से ही बस्तर के लोग बस्तर के गीतों के साथ ही ओडिया गीतों का भी भरपुर आनंद उठाते हैं। इस फिल्म में भी नए-नए ओडिया गीतों को लॉन्च किया गया है। निश्चित ही फिल्म और उनके गीत बस्तर के लोगों को पसंद आएंगे।

## संक्षिप्त समाचार

**भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री कर्मवीर सिंह ने की साय से मुलाकात**



जनता पार्टी, छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री (संगठन) कर्मवीर सिंह ने शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में हुई बैठक के दौरान विभिन्न संगठनात्मक विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान झारखंड भाजपा के प्रदेश महामंत्री (संगठन) पवन साय के साथ मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल भी उपस्थित रहे।

**आईएसएस तंबोली अरय्याज फकीरभाई बने आईआरडीआई के कार्यकारी निदेशक**

रायपुर। छत्तीसगढ़ कैडर के 2009 बैच के आईएसएस तंबोली अरय्याज फकीरभाई की भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीआई) में कार्यकारी निदेशक के पद पर नियुक्ति की गई है। यह नियुक्ति वित्तीय सेवा विभाग के अंतर्गत पदभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष के संयुक्त कार्यकाल या आगे आदेश तक प्रभावी होगी। डॉक्टर तंबोली अरय्याज फकीर भाई का जन्म 23 दिसंबर 1981 को महाराष्ट्र के पुणे जिले के बारामती तहसील के सोमेश्वर नगर गांव में हुआ था। उन्होंने अपने दूसरे प्रयास में यूपीएससी 75 वीं रैंक के साथ चूँक किया है। डॉक्टर तंबोली अरय्याज फकीर भाई का जन्म हुआ। यह गांव डॉक्टर तंबोली अरय्याज का निहाल है। यहां स्थित क्रापरिटिव शूगर फैक्ट्री में इनके नाना काम करते थे। डाक्टर अरय्याज का मूल गांव मुखुरी है, जो पुणे जिले के सिरूर तहसील में आता है। गांव के बाजू में ही जातेगांव है, जहां इनके पिता प्रथमरी शिक्षक थे। डॉ। तंबोली अरय्याज ने नौवीं से बारहवीं की पढ़ाई सिरूर से की। मैथ्स के साथ साईंस की पढ़ाई करने वाले तंबोली अरय्याज फकीर भाई ने 12वीं के बाद इंजीनियरिंग के कोर्स में एडमिशन लिया। तीन माह तक इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने एमबीबीएस में प्रवेश ले लिया। 2006 में उन्होंने पुणे से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की।

**सहायक शिक्षक भर्ती-2026 -2292 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी, परीक्षा आज**

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक भर्ती-2026 के अंतर्गत 2292 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 11 अक्टूबर 2026 को निर्धारित की गई है। इस बीच समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगता की चिन्हांकित श्रेणियों के संबंध में 11 सितंबर 2026 को संशोधित अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें सहायक शिक्षक पद के लिए पूर्ण दृष्टिबाधित (बी) श्रेणी को भी शामिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा 25 फरवरी 2026 को राज्य शासन के सभी विभागों के अंतर्गत विभिन्न संवर्गों के लिए दिव्यांगता की चिन्हांकित श्रेणियों की सूची जारी की गई थी। इस अधिसूचना में सहायक शिक्षक पद के लिए पूर्ण दृष्टिबाधित (बी) श्रेणी को चिन्हांकित नहीं किया गया था। ज्ञातव्य है कि 16 अप्रैल 2026 को सहायक शिक्षक के 2292 पदों पर भर्ती के लिए समाचार पत्रों में संक्षिप्त विज्ञापन प्रकाशित किया गया। वहीं 24 जुलाई 2026 को छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल की वेबसाइट पर विस्तृत विज्ञापन जारी किया गया। इस विज्ञापन में समाज कल्याण विभाग की 25 फरवरी 2026 की अधिसूचना के अनुरूप दिव्यांगता की श्रेणियों का उल्लेख किया गया था। उस समय पूर्ण दृष्टिबाधित (बी) श्रेणी को सहायक शिक्षक पद के लिए शामिल नहीं किया गया था।

**दुकर्म के मामले में बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने लिया सज़ान**

रायपुर। आमानाका थाना क्षेत्र में तीन साल की मासूम बच्ची के साथ कथित यौन अपराध के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने गंभीरता से सज़ान लिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने मामले में आरोपी परमानंद ध्रुव को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा के संज्ञान में मामला आने के बाद आयोग ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए संबंधित अधिकारियों को तलब कर मामले की तथ्यात्मक जानकारी मांगी है। आयोग द्वारा मामले में की गई कार्रवाई, पुलिस जांच की स्थिति और पीडित बच्ची को उपलब्ध कराई जा रही सहायता के संबंध में जानकारी ली जा रही है। मामले में पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 3 एवं 4 सहित धारा 75 बच्चों के प्रति क्रूरता और बाल शोषण के तहत कार्रवाई की स्थिति की भी समीक्षा की जा रही है। आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है कि मामले की जांच निष्पक्ष एवं प्रभावी ढंग से हो और पीडित बच्ची के अधिकारों की रक्षा के साथ उसे आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाए। आयोग ने स्पष्ट किया है कि बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मामले में संबंधित अधिकारियों से प्राप्त जानकारी और जांच की प्रगति के आधार पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

**गन्ना किसानों के हित में बड़ा फैसला : भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधिमंडल से चर्चा के बाद सीएम साय ने लिया महत्वपूर्ण निर्णय**

## अब 425 रुपए प्रति किंटल की दर से होगी गन्ने की खरीदी

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रदेश के गन्ना किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए शक्कर कारखानों में गन्ने की खरीदी अब 425 रुपए प्रति किंटल की दर से किए जाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्नदाता की खुशहाली ही समृद्ध छत्तीसगढ़ का आधार है। किसानों को उनकी मेहनत का बेहतर प्रतिफल मिले, खेती लाभकारी बने और किसान परिवार आर्थिक रूप से निरंतर सशक्त हों, इसके लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय से आज भारतीय किसान संघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य भेंट की। प्रतिनिधिमंडल में संगठन मंत्री श्री मनीष

शर्मा, महामंत्री श्री नवीन शेष सहित अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य शामिल थे। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव और श्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।

भेंट के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रतिनिधिमंडल के साथ प्रदेश के किसानों से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की। चर्चा के दौरान गन्ना उत्पादक किसानों के हितों से संबंधित विषय भी प्रमुखता से सामने आया। मुख्यमंत्री ने किसानों की भावनाओं और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर त्वरित पहल की और शक्कर कारखानों के लिए गन्ने की खरीदी 425 रुपए प्रति किंटल की दर से करने का निर्णय लिया।पेराई सत्र 2025- 26 में की गई खरीदी का भुगतान भी बढ़े हुए दर पर किया जाएगा।



मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने, कृषि लागत को कम करने तथा खेती को अधिक

लाभकारी बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार भी किसानों के हितों को अपनी नीतियों और निर्णयों के केंद्र में रखकर आगे बढ़ रही है। किसानों की आवश्यकताओं और समस्याओं के प्रति सरकार संवेदनशील है तथा किसान हित से जुड़े विषयों पर प्राथमिकता से निर्णय लिए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की

अर्थव्यवस्था और ग्रामीण समृद्धि में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। खेती-किसानी मजबूत होगी तो गांव मजबूत होंगे और गांवों की समृद्धि से ही छत्तीसगढ़ की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। राज्य सरकार का प्रयास है कि किसानों को उनकी उपज का उचित और बेहतर मूल्य मिले तथा कृषि उनके लिए सम्मानजनक और लाभकारी आजीविका का सशक्त माध्यम बने।

भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधिमंडल ने गन्ना किसानों के हित में लिए गए इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि इस निर्णय से प्रदेश के गन्ना उत्पादक किसानों को लाभ मिलेगा और उन्हें अपनी मेहनत का बेहतर प्रतिफल प्राप्त होगा।

**सीजेपी के प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री साय का बड़ा बयान, कहा-**

## वातावरण अशांत न हो इसलिए सरकार ने उठाए विशेष कदम

रायपुर। काकरोच जनता पार्टी के दिल्ली में प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले समय हुए आंदोलन में हजारों की संख्या में असामाजिक तत्व घुस गए थे। सरकार नहीं चाहेगी कि दोबारा ऐसी स्थिति बने और असामाजिक तत्वों के घुसने से वातावरण अशांत हो, इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विशेष कदम उठाए हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इसके साथ गन्ने की कीमत बढ़ाने पर कहा कि कवर्धा में किसान आंदोलित थे। कवर्धा गन्ना उत्पादक क्षेत्र है। किसान नेताओं से मुलाकात में गन्ने की कीमत को लेकर चर्चा हुई। पहले गन्ने की कीमत 355 रुपये प्रति किंटल थी, जिसे बढ़ाकर 425 रुपये प्रति किंटल किया

कांग्रेस लगातार सिमटती जा रही है। आने वाले समय में कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि वे ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, इसलिए वे सपना देखते रहें।

वहीं सीजेपी के कोलेर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि असामाजिक तत्वों ने विदेशी ताकतों के साथ मिलकर भारत को कमजोर करने की साजिश की है। इसी आशंका को ध्यान में रखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कांग्रेस को इस मामले में जवाब देना चाहिए। सोनिया गांधी भारत की नागरिक बनने से पहले दोर बन गई थी। इस तरह से घुसपैठियों का प्रवेश नहीं होना चाहिए।

## विश्वास, संवेदना और जिम्मेदारी की भावना से सराबोर है प्रथमेश हॉस्पिटल

**मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज करेंगे शुभारंभ**

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आगामी 11 अक्टूबर को प्रथमेश हॉस्पिटल के रूप में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक नए संस्थान का शुभारंभ होने जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने कारकर्मलों से हॉस्पिटल का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल समेत अनेक जनप्रतिनिधि व गणमान्य नागरिकों की गरिमामयी उपस्थिति होगी।

प्रथमेश हॉस्पिटल रायपुर के देवपुरी क्षेत्र में स्थापित किया गया है। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से इतर प्रथमेश हॉस्पिटल पूरी तरह डॉक्टरों द्वारा स्थापित और संचालित है। यह पहल चिकित्सकों और मरीजों के बीच विश्वास बढ़ाने तथा समाज के हर वर्ग



की सेवा करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। आज जब स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में बड़े कॉर्पोरेट घरानों का कब्जा बढ़ता जा रहा है, तब डॉक्टरों द्वारा संचालित यह मॉडल डॉक्टर और मरीज के बीच विश्वास के रिश्ते को मजबूत करेगा तथा चिकित्सा सेवा को फिर से सेवा, संवेदना और जिम्मेदारी के मूल मूल्यों से जोड़ेगा।

प्रथमेश हॉस्पिटल 1 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में फैले परिसर में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप 125 बिस्तरों के साथ शुरू किया जा रहा है,

जहाँ 1 लाख वर्ग फीट से अधिक पूर्णतः वातानुकूलित भवन में न्यूरोसाइसेस, कार्डियक साइसेस, वृमन एंड चाइल्ड केयर, ट्रामा एवं इमरजेंसी तथा फिजियोथेरेपी एवं रिहैबिलिटेशन के सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस के साथ 50+ बेड का मॉड्यूलर आईसीयू, 50 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर है। मध्य भारत की सबसे उन्नत कार्डियक यूनिट, संपूर्ण रेडियोलॉजी एवं पैथोलॉजी सुविधाएँ (एक्स-रे, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई), न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट, न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, प्लास्टिक एवं कॉस्मेटिक सर्जरी, पीडियाट्रिक्स एवं नियोनेटोलॉजी, क्रिटिकल केयर जैसे प्रमुख विभाग स्थापित किए गए हैं।

## रायपुर में सफाई व्यवस्था पर सचिव बोरा की नाराजगी गंदगी की फोटो दिखाकर अधिकारियों को लगाई फटकार

रायपुर। राजधानी रायपुर के गली-मोहल्लों से लेकर मुख्य सड़कों पर कूड़े के ढेर नजर आ जाएंगे। सफाई व्यवस्था को लेकर आम जनता में लगातार लापरवाही बरती जा रही है। पैदल चलने वालों को नाली से निकाले गए कचरे की दुर्गंध का सामना करना पड़ता है। रायपुर नगर निगम के कार्यों की समीक्षा में नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव सोनमणि बोरा ने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के कार्यों में गोलमोल जवाब प्रमुख सचिव बोरा ने अधिकारियों को नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि गरीबों के आवास में गुणवत्ताहीन काम और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके कार्यों में कोताही न बरतें। इसके अलावा शहर में सफा-सफाई की कमजोर व्यवस्था पर भी सचिव बोरा ने शहर में गंदगी की तस्वीरें दिखाते हुए नाराजगी जताई और सख्त हद्दयावत दी। लापरवाही बरतने पर दो अधिकारियों को कारण



बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।

प्रमुख सचिव बोरा ने मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना, अधोसंरचना मद और 15वें वित्त आयोग सहित सभी निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर तिमाही में कार्यों की अच्छी प्रगति दिखना चाहिए। उन्होंने निगम के अधिकारियों और अधिकारियों को विजन के साथ काम करते हुए निकट भविष्य में होने वाले कार्यों की रूपरेखा भी बनाकर रखने को कहा। उन्होंने कार्यों में गुणवत्ता और समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए।

प्रमुख सचिव बोरा ने रायपुर में बन रहे नए नालदा परिसर में पुराने नालदा परिसर की कमियाँ-खामियों को दूरकर आधुनिक परिसर और उच्च

व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नए भवन में दिव्यांगजनों के लिए भी सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा।

बैठक में निगम द्वारा संचालित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में बिजली की खपत को कम करने पर भी चर्चा की गई। प्रमुख सचिव ने एनर्जी इफिफिएंट तकनीकों का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जन सुविधाओं को नागरिकों तक पहुंचाने, जरूरत के अनुसार उहड़ दस्तावेज उपलब्ध कराने और राजस्व वसूली में डिजिटल व आधुनिक तकनीकों को अपनाने को कहा। इससे नागरिकों की सुविधाएं बढ़ेंगी और उन्हें तेजी से नागरिक सेवाओं का लाभ मिल सकेगा।

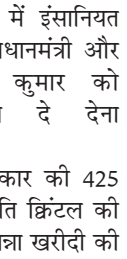
प्रमुख सचिव ने मिशन अमृत 2.0 के तहत रायपुर के शीतला तालाब के पुनरोद्धार और सौंदर्यीकरण के कार्यों को आगामी मार्च तक पूर्ण करने के

**दिल्ली में प्रदर्शन: पीसीसी चीफ ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा-**

## दिल्ली को बना दिया जेल, डरी हुई है सरकार: बैज

रायपुर। दिल्ली प्रदर्शन को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक धरना को रोकने के लिए दिल्ली को जेल बना दिया है। हर तरफ घेराबंदी है, सभी सड़कों को बंद कर दिया गया है। हर गाड़ी की चेकिंग हो रही है। एम्बुलेंस तक को बक्शा नहीं जा रहा है। दरअसल, सरकार डरी हुई है, और जब तक ज्ञानेश कुमार और पीएम मोदी का इस्तीफा नहीं मिलता, तब तक प्रदर्शन चलता रहेगा।

दीपक बैज ने मीडिया से चर्चा में भाजपा के कांग्रेस पर संविधान को हाईजैक करने की कोशिश के आरोप पर कहा कि केंद्र सरकार ने लोकतंत्र को खत्म किया। सरकार ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर संविधान को कुचलने का काम किया, इसलिए आज आम जनता सड़क पर प्रदर्शन कर रही है।



रायपुर में इसानियत है तो प्रधानमंत्री और ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए।

सरकार की 425 रुपए प्रति किंटल की दर से गन्ना खरीदी की घोषणा पर दीपक बैज ने कहा कि किसानों की स्थिति छत्तीसगढ़ में खराब है। मजदूरों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। यह सिर्फ घोषणा है, अब भी किसानों का कोई भला नहीं होगा। किसानों को ठगने का काम सरकार कर रही है।

वहीं रोजगार मेले को लेकर बैज ने कहा कि सरकार दावा कर रही है कि करीब 10 हजार नौकरियां दी है। अब तक 1 लाख से अधिक पद खाली है। 5 हजार पद भी सरकार नहीं भर पाई है। सरकार प्रदेश के युवाओं को

रोजगार के नाम पर झूठ बोल रही है। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के दौरे को लेकर बैज ने कहा कि देश में इमरजेंसी के हालात हैं, और यहां नौटंकी कर रहे हैं। ये पूरी तरह से सरकार की फिजूल खर्ची है। इस सरकार में रेल व्यवस्था बहाल हो चुकी है। पहले दिल्ली से ट्रेनों को चालू करें, फिर छत्तीसगढ़ में नई ट्रेन का उद्घाटन करें।

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ प्रवास को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि श्याम बिहारी जायसवाल पहले अपने विभागों को संभालें। जंगल उजड़ रहे हैं, चहेते उद्योगपतियों को जल, जंगल, जमीन सौंप रहे हैं। पहले श्याम बिहारी जायसवाल बताएं कि यह सब सही है क्या?

## टी 20 मैच की तैयारियों को लेकर कलेक्टर ने ली बैठक

रायपुर। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने 16, 18 एवं 20 अक्टूबर को राजधानी के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होने वाले इंडिया 1हा जिम्बाब्वे टी 20 मैच की तैयारियों को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ के साथ बैठक ली।

कलेक्टर डॉ. सिंह ने कहा कि यह छत्तीसगढ़ के लिए महत्वपूर्ण आयोजन है। पाकिंग की समुचित व्यवस्था की जाए तथा सामानों की ओवररेटिंग न हो। पुलिस प्रशासन से समन्वय कर सुरक्षा एवं ट्रैफिक के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। उन्होंने कहा कि मैदान में खिलाड़ियों के साथ दर्शकों के लिए आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित रहें। प्रशासन की एसओपी का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए। आपदा के समय क्या किया जाए, इसकी कार्ययोजना पहले से तैयार रखें। डॉ. सिंह ने कहा कि आग से बचाव के लिए आवश्यक उपकरणों का अनिवार्य रूप से



इंतजाम किया जाए तथा जिला सेनानी से समन्वय स्थापित कर उपकरणों का पूर्व परीक्षण कर लिया जाए। सभी दर्शकों की सुविधाजनक आवाजाही सुनिश्चित की जाए और मेडिकल सुविधा का अनिवार्य रूप से इंतजाम किया जाए। क्रिकेट संघ के प्रतिनिधियों ने बताया कि इस बार केवल ऑनलाइन माध्यम से टिकट की बिक्री की जा रही है। बैठक में नगर निगम आयुक्त श्री संवित मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग की संचालक श्रीमती आकांक्षा खलखो, रायपुर ग्रामीण एएसपी श्री अभिषेक झा, एडीएम श्री उमाशंकर बंदे, छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ एवं बीसीसीआई के प्रतिनिधि सहित अग्र्य अधिकारी उपस्थित थे।

# एसआईआर गतिरोध : आखिर इस मर्ज की दवा क्या है?

**डॉ. योगेन्द्र श्रीवास्तव**

देश भर की वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एस आई आर) के मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अभियान जोरों पर है और जैन जी के साथ अब विपक्ष भी लामबन्द हो चुका है। बातचीत के जरिए किसी मामले को निबटाने में मोदी सरकार का कोई इरादा नहीं होता इसलिए 10 अक्टूबर का प्रदर्शन रोकने के लिये सत्तासीन बीजेपी सरकार ने दिल्ली की किलेबंदी कुछ इस तरह की जैसे कोई सशस्त्र हमला होने वाला है। पुलिस प्रशासन के जरूरत से ज्यादा इंतजामात पर सुप्रीम कोर्ट ने तलख् टिप्पणी को कि मक्खी को मारने के लिये हथौड़े का इस्तेमाल जायज नहीं। उधर इंडी अलायंस ने राष्ट्रपति से मुलाकात करके ईवीएम हटाने का प्रस्ताव दिया और पुरानी बैलट पेपर पद्धति से चुनाव की माँग की। सोमवार को वे सुप्रीम कोर्ट जाकर भारत के चीफ जस्टिस को भी ज्ञापन देने वाले हैं। लेकिन इस हंगामे के बीच बहुत सी पेचीदगियां सामने आई हैं। मसलन राष्ट्रपति अथवा भारत के चीफ जस्टिस भी मुख्य चुनाव आयुक्त को संवैधानिक पर से हटाने का सीधे आदेश नहीं दे सकते क्योंकि इसकी प्रक्रिया काफी लम्बी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(5) के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी प्रक्रिया से पद से हटया जा सकता है जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटया जाता है। यद्यपि वर्ष 2023 में मोदी सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया में संशोधन कर दिया था परन्तु किसी पदासीन मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने हेतु पूर्व में संविधान में उल्लिखित प्रक्रिया का ही अनुररण किया गया। चूँकि ये राजनीतिक अथवा प्रशासनिक पद नहीं इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने के आधारों को सख्ती से कदाचार या अक्षमता तक सीमित किया गया है जिनका सिद्ध होना अनिवार्य है। राजनीतिक चर्चाओं और अखबारों में व्यापक रूप से महाभियोग शब्द का प्रयोग किया जाता है परन्तु न्यायाधीशों और मुख्य निर्वाचन आयोग के लिये उचित शब्द निष्कासन है जिसके लिये लोकसभा के 100 या राज्यसभा के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ प्रस्ताव संबंधित सदन के पीठासीन अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है जो प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि आरोप स्वीकृत हों तो जाँच हेतु सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में त्रिसदस्यीय समिति बनती है। यदि उक्त समिति मुख्य निर्वाचन आयुक्त  को कदाचार या अक्षमता का दोषी पाती है, तो रिपोर्ट वापस सदन में प्रस्तुत की जाती है। प्रस्ताव पारित करने हेतु दोनों सदनों में विशेष बहुमत से समर्थन प्राप्त होना आवश्यक है। पारित होने की स्थिति में राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का आधिकारिक आदेश जारी करते हैं। ऐसी परिस्थिति में बाहिर है कि अगर ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते तो उन्हें सीधे हटाना असम्भव है। उनके निष्कासन की निर्धारित प्रक्रिया से भी उन्हें हटया जाना मुमकिन नहीं क्योंकि लोकसभा या राज्यसभा में विपक्ष के पास वांछित बहुमत नहीं। फिर उनका कार्य कदाचार या अक्षमता के दायरे में भी नहीं आता। अगर इण्डियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पर भरोसा किया जाये तो ज्यादा से ज्यादा मनमानी का आरोप बनता है जो पूरी जाँच में शायद ही टिक सके। फिर भारत में जाँच इतनी लम्बी खिंची है कि तब तक शायद ज्ञानेश कुमार अपना कार्यकाल ही पूरा कर लें। फिर एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या उनके इस्तीफा देने से ही सब कुछ सुधर जायेगा। मोदी सरकार के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सम्बन्धी 2023 के संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं। ऐसे में दोबारा किसी की नियुक्ति भी वही सरकार करेगी।

**भारतीय दार्शनिक सम्प्रदाय**

## 18- जैन दर्शन

**गतांक से आगे...**

जैन दर्शन ने भारतीय दर्शन को एक नया दृष्टि कोण दिया जिसे अनेकान्तवाद कहते हैं। और वही अनेकान्तवाद तर्क या न्याय में सप्तभङ्गूनय अथवा स्याद्वाद का रूप ग्रहण कर लेता है। इस लिये जैनदर्शन के तत्त्व को समझने के लिये अनेकान्तवाद का स्वरूप समझना आवश्यक है।

एकान्त का अर्थ है कि एक ही अन्त अर्थात् किसी विषय में एक ही अन्त अर्थात् एक ही सिद्धान्त हो। अधिकांश दर्शनशास्त्र एकान्तवादी हैं अर्थात् किसी वस्तु के स्वरूप के विषय में एक ही निश्चित सिद्धान्त मानते हैं। जैन दार्शनिक कहते हैं कि किसी वस्तु का एक ही स्वरूप हो यह ठीक नहीं, उसके भिन्न भिन्न दृष्टियों से अनेक स्वरूप हो सकते हैं और वे भिन्न भिन्न दृष्टियों के संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं। जहां एक ओर भिन्न भिन्न दार्शनिक सम्प्रदाय के लोग परस्पर एक दूसरे का

खण्डन करते हुए कलह करते हैं वहां जैनों की यह अनेकान्त दृष्टि उन भिन्न भिन्न मतों में समन्वय, सामञ्जस्य या सङ्गति स्थापित करती है। इस अनेकान्तवाद को उदा-हरण के द्वारा कुछ अधिक स्पष्ट समझने की आवश्यकता है।

प्रत्येक वस्तु को हम उसके सामान्य और विशेष रूप में देख सकते हैं। उदाहरणार्थ, एक घट को हम एक घट व्यक्ति के रूप में देख सकते हैं, तथा सामान्य घट के रूप में देख सकते हैं, या और भी बड़ा सामान्यरूप लेकर पृथ्वी के रूप में या द्रव्य के रूप में और परम-सामान्य दृष्टि करने पर सत्ता के रूप में देख सकते हैं। इन विशेष और सामान्य रूपों में कौन यथार्थ है या परम सत्य है? दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में उनके दो परस्पर सर्वथा विपरीत उत्तर मिलते हैं। वेदान्त के अनुसार सामान्यरूप ही यथार्थ है, और विशेष रूप भ्रम मात्र हैं।

**क्रमशः ...**



# ज्ञान/मीमांसा

# विपक्ष के लिए ज्ञानेश कुमार को हटवाना क्या आसान होगा?

**सचिन शर्मा**

देश के कई प्रमुख विपक्षी दलों ने इस समय भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ देश भर में मोर्चा खोल रखा है। वो सभी ज्ञानेश कुमार को पद से हटवाना चाहते हैं। उनका एक और मुद्दे को लेकर भी प्रखर विरोध है। वह है स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (एसआईआर)। विपक्षी दल इसमें धांधली की शिकायत कर रहे हैं। इन मुद्दों को लेकर विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के अलावा कांक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) और वाम दलों का छात्र संगठन आइसा (ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन) भी एक्शन में हैं। वो भी समान मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। यह सब हो रहा है एक प्रमुख अंग्रेजी दैनिक अखबार की उस रिपोर्ट को आधार बनाकर जिसमें दावा किया गया है कि केन्द्रीय चुनाव आयोग के कुल तीन आयुक्तों में से दो सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों के दौरान 14 बार ज्ञानेश कुमार के फैसलों पर लिखित में आपत्तियां दर्ज कराई थीं। एक अखबार की रिपोर्ट के आधार पर विपक्ष का इतने बड़े आंदोलन में कूद पड़ना वो भी पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के कुछ महीने पहले क्या सत्तारूढ़ दल भाजपा को राहत दे रहा है या वो वाकई मुश्किल में है, आइए समझते हैं।

अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी 23 सितंबर की एक खोजी रिपोर्ट में विस्तार से बताया था कि बीते 10 महीनों में मुख्य चुनाव आयुक्त के कई फैसलों से बाकी के दो चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी असहमत थे। यह असहमति उन्होंने सिर्फ बोलकर ही नहीं बल्कि लिखकर भी जताई। असहमति के मुख्य मुद्दों में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (एसआईआर) की प्रक्रिया शामिल थी। इस प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले फार्म-6 पर भी असहमति जताई गई थी। नए मतदाताओं के लिए इस्तेमाल में आने वाले इस फार्म-6 में जो संशोधन प्रस्तावित थे उन पर दोनों ही चुनाव आयुक्त सहमत नहीं थे। खासतौर से उस बिंदु से जिसमें नए मतदाताओं से उनके दादा-दादी या नाना-नानी के पुराने चुनावी रिकार्ड्स का ब्यौरा उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। इसके अलावा सभी चुनावी रिकार्ड्स को भी दिल्ली मुख्यालय में केन्द्रीकृत करने का भी विरोध जताया गया था। इस तरह से कुल 14 बार दोनों आयुक्तों ने लिखित में ज्ञानेश कुमार को बताया था कि वो उनकी बगैर अनुशंसा और जानकारी के



तमाम निर्णय ले रहे हैं। इस रिपोर्ट से विपक्षी दलों की बांछें खिल गईं। वो पहले से ही ज्ञानेश कुमार का विरोध कर रहे थे। इंटेंसिव रिविजन को भी गलत ठहरा रहे थे। कांग्रेस इसे लगातार वोट चोरी की संज्ञा देती रही है।

जुलाई में जंतर-मंतर पर हुए कांक्रोच जनता पार्टी के छात्र आंदोलन के बाद केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धमेन्द्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया था। प्रधानमंत्री ने भी उनका इस्तीफा तुरंत स्वीकार करके उस आंदोलन को ठंडा कर दिया था लेकिन इस बार मामला उतना आसान नहीं है। केरल कैडर के 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर ज्ञानेश कुमार इस समय भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। उनकी नियुक्ति 19 फरवरी 2025 को हुई थी। उनसे केन्द्र सरकार इस्तीफा नहीं मांग सकती है। उन्हें हटाना या हटवाना उतनी ही टेढ़ी खीर है जितना सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को हटाना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 की छतरी चुनाव आयुक्त को मिली होती है। मतलब उनके कार्यकाल को विशेष %सुरक्षा% प्राप्त होती है ताकि उनसे अप्रसन्न रहने वाली कार्यपालिका उन पर कोई दबाव ना बना सके। उन्हें सिर्फ अक्षमता और सिद्ध दुर्व्यवहार की वजहों से हटया जा सकता है। हटाने की प्रक्रिया के तहत संसद के दोनों सदनों से विशेष प्रस्ताव पारित करवाना होता है। उसके बाद राष्ट्रपति को उस प्रस्ताव को स्वीकार कर उस पर आदेश देना होता है। संसद के दोनों सदनों में इस प्रस्ताव के पेश होने से पहले लोकसभा में इस पर कम से कम 100 सांसदों और राज्यसभा में 50 सांसदों के हस्ताक्षरों की जरूरत होती है। इसके बाद जांच समिति का गठन और दोषसिद्धि के बाद संसद के दोनों सदनों में मतदान होता है। विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजे जाने का प्रावधान है। आखिर में राष्ट्रपति अगर चाहें तो मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का आदेश दे सकते हैं।

विपक्षी दल चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्तों को लेकर कोई पहली बार खफा नहीं हुए हैं। जब उन्हें अपनी पसंद के नतीजे नहीं मिलते

## नारी सशक्तिकरण का पर्व है नवरात्रि

**रमेश सर्राफ धमोरा**

भारत त्योहारों का देश है जहां हर पर्व का अपना एक विशेष महत्व और पौराणिक कथा होती है। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण पर्व है नवरात्रि । यह पर्व मां दुर्गा के नौ रूपों की उपासना और शक्ति आराधना का प्रतीक है। नवरात्रि मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा और आराधना के लिए समर्पित है। जिन्हें शक्ति, साहस, और नारी सशक्तिकरण का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि का अर्थ है नौ रातें। इस दौरान भक्त देवी दुर्गा की विशेष पूजा करते हैं, उपवास रखते हैं, और भक्ति में लीन रहते हैं। इन नौ दिनों का भारतीय धर्म एवं दर्शन में ऐतिहासिक महत्व है और इन्हीं दिनों में बहुत सी दिव्य घटनाओं के घटने की जानकारी हिन्दू पौराणिक ग्रन्थों में मिलती है। माता के इन नौ रूपों को नवदुर्गा के

नाम से भी जाना जाता है जो इस प्रकार हैं –शैलपुत्री, ब्रह्माचारिणी, चन्द्रघन्टा, कूष्माण्डा, स्कन्द माता, कात्यायनि, कालरात्रि, महागौरी और सिध्दिदात्री।

नवरात्रि का त्योहार एक बार वसंत ऋतु के दौरान चैत्र नवरात्रि और शरद ऋतु के दौरान शरद नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। शरद नवरात्रि अश्विन के महीने के दौरान मनाई जाती है जो आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर में आती है। वहीं चैत्र नवरात्रि हिन्दू कैलेंडर के चैत्र महीने के दौरान मनाई जाती है। चैत्र नवरात्रि आमतौर पर मार्च या अप्रैल महीने में मनाई जाती है। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है नौ रातें। इन नौ रातों और दस दिनों के दौरान शक्ति- देवी के नौ रूपों की पूजा की



इंसान अपने अंदर की मूलभूत अच्छाइयों से नकारात्मकता पर विजय प्राप्ती और स्वयं के अलौकिक स्वरूप से साक्षात्कार कैसे कर सकता है। भारतीय जन-जीवन में धर्म की महत्ता अपरम्पार है। यह भारत की गंगा-जमुना तहजीब का ही नतीजा है कि सब धर्मों को मानने वाले लोग अपने-अपने धर्म को मानते हुए इस देश में भाईचारे की भावना के साथ सदियों से एक साथ रहते चले आ रहे हैं। यही कारण है की पूरे विश्व में भारत की धर्म व संस्कृति

जाती है। दसवां दिन दशहरा के नाम से प्रसिद्ध है।

नवरात्रि से हमें अधर्म पर धर्म और बुराई पर अच्छाई के जीत की सीख मिलती हैं। यह हमें बताती है की नवरात्रि हमें अंदर की मूलभूत अच्छाइयों से नकारात्मकता पर विजय प्राप्ती और स्वयं के अलौकिक स्वरूप से साक्षात्कार कैसे कर सकता है। भारतीय जन-जीवन में धर्म की महत्ता अपरम्पार है। यह भारत की गंगा-जमुना तहजीब का ही नतीजा है कि सब धर्मों को मानने वाले लोग अपने-अपने धर्म को मानते हुए इस देश में भाईचारे की भावना के साथ सदियों से एक साथ रहते चले आ रहे हैं। यही कारण है की पूरे विश्व में भारत की धर्म व संस्कृति

सर्वोत्तम मानी गयी है। विभिन्न धर्मों के साथ जुड़े कई पर्व भी है जिसे भारत के कोने – कोने में श्रध्दा, भक्ति और धूमधाम से मनाया जाता है। उन्ही में से एक है नवरात्रि। वसन्त की शुरुआत और शरद ऋतु की शुरुआत, जलवायु और सूरज के प्रभावों का महत्वपूर्ण संगम माना जाता है। इन दो समय मां दुर्गा की पूजा के लिए पवित्र अवसर माने जाते है। त्योहार की तिथियां चन्द्र कैलेंडर के अनुसार निर्धारित होती हैं। यह पूजा वैदिक युग से पहले प्रागैतिहासिक काल से है। नवरात्रि के पहले तीन दिन देवी दुर्गा की पूजा करने के लिए समर्पित किए गए हैं। यह पूजा उनकी ऊर्जा और शक्ति को की जाती है। प्रत्येक दिन दुर्गा के एक अलग रूप को समर्पित है। नवरात्रि वर्ष में चार बार आता है। चैत्र, आषाढ़, अश्विन, पौष प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है।

# वी विल डू इट-140 करोड़ देशवासियों का सामूहिक संकल्प

**विश्वास कैलाश सारंग**

भारत की विकास यात्रा आज उस मुकाम पर पहुंच चुकी है, जहां दुनिया भारत को केवल संभावनाओं वाले देश के रूप में नहीं बल्कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता रखने वाली एक सशक्त शक्ति के रूप में देख रही है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का वी विल डू इट का मंत्र देशवासियों के भीतर नए आत्मविश्वास, नई ऊर्जा और बड़े संकल्प का संचार करता है। 7 अक्टूबर को अपने सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र के सामने भविष्य के भारत की एक ऐसी तस्वीर रखी जिसमें लक्ष्य छोटे नहीं बल्कि विराट हैं। सपने सीमित नहीं बल्कि वैश्विक हैं और उन्हें पूरा करने का विश्वास 140 करोड़ देशवासियों की सामूहिक संकल्प में है।

प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अब असंभव समझे जाने वाले लक्ष्यों से पीछे हटने वाला नहीं है। वी विल डू इट प्रधानमंत्री जी का यह मंत्र भारत की उस बदलती मानसिकता का प्रतीक है, जिसमें चुनौतियों को बाधा नहीं बल्कि अवसर के रूप में देखने का आत्मविश्वास पैदा हुआ है। हम कर सकते हैं से आगे बढ़कर हम करके दिखाएंगे का भाव ही इस मंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है। प्रधानमंत्री जी ने इन लक्ष्यों को सामने रखा उनमें 2047 तक विकसित भारत, विश्व की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में भारत का स्थान, आत्मनिर्भर भारत, भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, ओलंपिक की मेजबानी और अंतरिक्ष के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूना शामिल हैं। हर लक्ष्य के साथ उनका उद्धोष वी विल डू इट देश की सामूहिक संकल्प की इच्छाशक्ति को अभिव्यक्त करता है।

2047 में भारत अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएगा। यह केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं बल्कि वर्तमान पीढ़ी के सामने इतिहास रचने का अवसर है। आज की युवा पीढ़ी के सामने यह जिम्मेदारी है कि वह ऐसा भारत बनाए जो आर्थिक



रूप से मजबूत हो, तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर हो, सामाजिक रूप से सशक्त हो और वैश्विक स्तर पर नेतृत्व करने की क्षमता रखता हो।

प्रधानमंत्री जी ने इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए कहा कि आज सवाल केवल यह नहीं है कि 2047 में भारत को कहां पहुंचना है बल्कि यह है कि उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आज से क्या करना है? यही विचार वी विल डू इट को भविष्य के संकल्प से वर्तमान के कर्म से जोड़ता है। आत्मनिर्भर भारत का अर्थ दुनिया से अलग होना नहीं बल्कि दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाते हुए अपनी क्षमताओं को मजबूत करना है। आज भारत मोबाइल निर्माण से लेकर रक्षा उत्पादन, डिजिटल तकनीक से लेकर अंतरिक्ष अनुसंधान और नवीकरणीय ऊर्जा से लेकर स्टार्टअप इनोवैशियन स्टार तक अनेक क्षेत्रों में अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है। प्रधानमंत्री जी के वी विल डू इट का संदेश इसी आत्मविश्वास को और मजबूत करता है कि भारत केवल दूसरों से सीखने वाला देश नहीं बल्कि दुनिया को सिखाने वाला देश बने। यह आत्मविश्वास उस भारत का है जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ वैश्विक बाजार के लिए भी उत्पादन करने की क्षमता रखता है।

भारत की विशाल युवा आबादी, प्रतिभा, तकनीकी क्षमता और बड़ा घरेलू बाजार उसे वैश्विक

मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्वाभाविक रूप से सक्षम बनाते हैं। मेक इन इंडिया से शुरू हुई सोच अब मेक फॉर द वर्ल्ड की दिशा में आगे बढ़ रही है। भारत में

निर्मित उत्पाद जब दुनिया के बाजारों में अपनी पहचान बनाते हैं तो यह केवल आर्थिक उपलब्धि नहीं होती बल्कि भारतीय प्रतिभा और सामर्थ्य पर दुनिया के बढ़ते विश्वास का प्रमाण भी होती है। प्रधानमंत्री जी ने इसी संदर्भ में बड़े लक्ष्यों की आवश्यकता पर जोर दिया है। उनका संदेश स्पष्ट है कि यदि लक्ष्य बड़ा होगा तो प्रयास भी बड़ा होगा और परिणाम भी असाधारण प्राप्त होंगे।

प्रधानमंत्री जी के वी विल डू इट मंत्र में भारत की खेल शक्ति के विस्तार का संकल्प भी दिखाई देता है। ओलंपिक की मेजबानी का लक्ष्य केवल एक अंतरराष्ट्रीय आयोजन की आकांक्षा नहीं है बल्कि भारत को वैश्विक खेल शक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आज देश में खेल अधीनसंचना का विस्तार हो रहा है। छोटे शहरों और गांवों से प्रतिभाएं सामने आ रही हैं और खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। गांव से ग्लोबल तक पहुंचती भारतीय खेल प्रतिभा इस विश्वास को मजबूत करती है कि यदि अवसर, संसाधन और सही मार्गदर्शन मिले तो भारत के युवा किसी भी वैश्विक मंच पर तिरों की शान बढ़ा सकते हैं।

जिस देश ने कभी अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत सीमित संसाधनों के साथ की थी, वही भारत आज चंद्रमा पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है और

अंतरिक्ष के क्षेत्र में नई महत्वाकांक्षाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी का अंतरिक्ष में भारत की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का संकल्प यह दर्शाता है कि भारत की आकांक्षाएं अब धरती की सीमाओं तक सीमित नहीं हैं।

प्रधानमंत्री जी के संदेश का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि उन्होंने इन लक्ष्यों की जिम्मेदारी केवल सरकार पर नहीं छोड़ी है। उन्होंने देश की 140 करोड़ आबादी को भारत की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है। भारत की हर समस्या के समाधान में करोड़ों भारतीयों की क्षमता जुड़ी है। किसान, युवा, महिला, वैज्ञानिक, उद्यमी, श्रमिक, खिलाड़ी, शिक्षक, स्टार्टअप संस्थापक और देश का प्रत्येक नागरिक विकासित भारत की यात्रा का भागीदार है। यही कारण है कि वी विल डू इट में वी सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। यह मैं करूंगा का नहीं बल्कि हम करेंगे का सामूहिक मंत्र है।

भारत के पास युवा शक्ति है, विशाल बाजार है, तकनीकी क्षमता है, लोकतांत्रिक मजबूती है और वैश्विक स्तर पर बढ़ता प्रभाव है। इसलिए आज भारत के सामने छोटे सपने देखने का समय नहीं है बल्कि बड़े लक्ष्य तय करने और उन्हें पूरा करने के लिए पूरी शक्ति से जुट जाने का समय है। वी विल डू इट की वास्तविक शक्ति केवल इसे बोलने में नहीं बल्कि इसे अपने जीवन और कर्म में उतारने में है। 2047 का विकासित भारत किसी एक सरकार, एक संस्था या एक वर्ग के प्रयास से नहीं बनएगा। इसका लिए प्रत्येक नागरिक को अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता का संकल्प लेना होगा। एक विद्यार्थी बेहतर शिक्षा का संकल्प ले, युवा नवाचार का संकल्प ले, किसान आधुनिक कृषि का संकल्प ले, उद्योग आत्मनिर्भर उत्पादन का संकल्प लें, खिलाड़ी विश्वस्तरीय प्रदर्शन का संकल्प लें और प्रत्येक नागरिक राष्ट्रहित को अपने व्यक्तिगत कर्तव्य से जोड़े तो सामूहिक रूप से यही छोटे-छोटे संकल्प विकासित भारत की विराट नींव बनेंगे। प्रधानमंत्री जी का वी विल डू इट मंत्र देश की इसी सामूहिक शक्ति को जगाने का प्रयास है।

# टीएन शेषन-ज्ञानेश कुमार: एक के दौर में बदली पहचान, दूसरे के दौर में क्यों उठे सवाल!

#### सत्येंद्र प्रताप सिंह

भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त का पद संविधान बनने के साथ ही अस्तित्व में आ गया था। अधिकार भी थे और जिम्मेदारियां भी। लेकिन आम मतदाता के बीच इस पद की ताकत का अहसास किसे था? शेषन से पहले नौ मुख्य चुनाव आयुक्त इस पद पर रह चुके थे, मगर उनका नाम आम राजनीतिक चर्चा का हिस्सा नहीं बना।12 दिसंबर 1990 को देश के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने टीएन शेषन ने तस्वीर बदल दी। उन्होंने चुनाव आयोग को सिर्फ चुनाव कराने वाली संस्था के बजाय चुनावी व्यवस्था पर निगरानी रखने वाली प्रभावशाली संवैधानिक संस्था के रूप में सामने रखा।

आयोग के आधिकारिक दस्तावेज भी उनके कार्यकाल में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कठोर क्रियावचन और चुनाव पर्यवेक्षकों की भूमिका बढ़ने को रेखांकित करते हैं। यही वह दौर था जब देश ने जाना कि मुख्य चुनाव आयुक्त चाहे तो राजनीतिक दलों की भी चुनावी नियमों के सामने झुका सकता है। शेषन का दौर ऐसे समय आया जब चुनावों में बाहुबल, बूथ कैप्चरिंग, फर्जी मतदान और हिंसा बड़े सवाल थे। खासकर बिहार के चुनावों की बदनामी देशभर में थी। शेषन ने इसे चुनावी व्यवस्था की मजबूरी मानने से इनकार किया। उनके कार्यकाल में जहां गड़बड़ी की आशंका गंभीर थी, वहां मतदान स्थगित या रद्द करने जैसे कदम उठाए गए। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया और चुनाव प्रक्रिया की निगरानी बढ़ाई गई। शेषन का संदेश साफ था बूथ पर कब्जा करने वाला कितना भी ताकतवर क्यों न हो, चुनाव आयोग उससे बड़ी संवैधानिक ताकत है। यही कारण था कि शेषन का नाम सिर्फ चुनाव आयोग के दफ्तर तक सीमित नहीं रहा। गांव के मतदाता से

लेकर दिल्ली के सत्ता गलियारों तक उनकी चर्चा होने लगी।

आज चुनाव आते ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता की चर्चा आम बात है। लेकिन इसे चुनावी राजनीति की वास्तविक ताकत बनाने में शेषन के दौर की बड़ी भूमिका रही। आयोग के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, शेषन की रणनीति आचार संहिता को कठोरता से लागू करने के साथ उसका व्यापक प्रचार करने की थी। सरकारी मशिनरी के दुरुपयोग से लेकर चुनाव प्रचार के तौर-तरीकों तक पर निगरानी बढ़ी। नेताओं और उम्मीदवारों को यह संदेश मिला कि चुनाव के दौरान सत्ता में होना नियमों से ऊपर होने का अधिकार नहीं देता। शेषन की सख्ती सिर्फ बड़े संवैधानिक मुद्दों तक सीमित नहीं थी। चुनाव प्रचार की पूरी संस्कृति को नियमों के दायरे में लाने की कोशिश हुई। उम्मीदवारों के खर्च, वाहनों के इस्तेमाल और चुनाव प्रचार में सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग पर निगरानी बढ़ी।

आज मतदान के दिन वाहनों के इस्तेमाल को लेकर जो विस्तृत नियम दिखाई देते हैं, उनकी राजनीतिक स्वीकार्यता की जमीन भी उसी दौर में मजबूत हुई। सवाल यह था कि क्या चुनाव गरीब और सामान्य उम्मीदवार के लिए भी वही होना चाहिए जो बड़े राजनीतिक दल और धनबल वाले उम्मीदवार के लिए है? शेषन का जवाब कार्रवाई के जरिए सामने आया। फर्जी मतदान पर रोक के लिए फोटो मतदाता पहचान-पत्र की दिशा में भी शेषन के कार्यकाल में निर्णायक पहल हुई। शुरुआत में इसका विरोध हुआ, लेकिन आगे चलकर फोटो पहचान-पत्र चुनावी व्यवस्था का अहम हिस्सा बना। इसी तरह चुनाव पर्यवेक्षकों की भूमिका को भी मजबूत किया गया। चुनाव आयोग के आधिकारिक



इतिहास के अनुसार, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की कोशिश में पर्यवेक्षकों की भूमिका बढ़ी और 1996 में उन्हें वैधानिक आधार मिला। अर्थात शेषन की विरासत सिर्फ ‘सख्त अफसर’ की नहीं थी। उन्होंने चुनाव आयोग की संस्थागत क्षमता को जमीन पर उतारने की कोशिश की।

करीब तीन दशक बाद मुख्य चुनाव आयुक्त का पद फिर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में है। ज्ञानेश कुमार देश के 26वें सीईसी हैं। लेकिन इस बार कहानी अलग है। उनके कार्यकाल में सबसे बड़ा विवाद एसआईआर यानी स्पेशल रेंटेंसिव रिविजन को लेकर खड़ा हुआ। मतदाता सूची को शुद्ध करना और अपात्र या गलत नामों को हटाना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी का हिस्सा है। लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया, नामों को जोड़ने-काटने, नए मतदाताओं के लिए दस्तावेजी शर्तों और आयोग की निर्णय प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठे। सितंबर 2026 में इंडियन एक्सप्रेस की एक जांच में दावा किया गया कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले दस महीनों में कम से कम 14 बार आयोग के फैसलों पर लिखित आपत्तियां दर्ज कीं।

रिपोर्ट में नए मतदाताओं को जोड़ने, नाम हटाने और मतदाता डेटा से जुड़े फैसलों पर भी सवालों का उल्लेख किया गया। सबसे चर्चित विवादों में नया फार्म-6 भी शामिल रहा। यह नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें एसआईआर से जुड़े सवाल जोड़े गए, जिनमें पुराने चुनावी रोल में आवेदक, माता-पिता या दादा-दादी के नाम से संबंधित जानकारी मांगी गई। दोनों चुनाव आयुक्तों ने इसे कथित तौर पर ‘illegal’ और ‘unauthorised’ बताते हुए आपत्ति जताई।

यहां विवाद सिर्फ फॉर्म का नहीं था। सवाल यह बना कि मतदाता बनने की प्रक्रिया कितनी सरल होनी चाहिए और चुनाव आयोग प्रशासनिक प्रक्रिया में कितनी दूर तक बदलाव कर सकता है? लेकिन तस्वीर का दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। चुनाव आयोग ने इन आपत्तियों के अस्तित्व से इनकार नहीं किया, लेकिन कहा कि अलग-अलग राय निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा हैं और पिछले एक वर्ष में आयोग के सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए। इसलिए इन आरोपों को अंतिम निष्कर्ष की तरह पेश करना उचित नहीं होगा। विवाद का वास्तविक परीक्षण अब कानूनी और संस्थागत स्तर पर हो रहा है।5 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने सीईसी ज्ञानेश कुमार की कार्यप्रणाली और एसआईआर से जुड़े मामले में नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि कुछ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना लिए गए; हालांकि अदालत ने तत्काल सीईसी को पद से हटाने या निलंबित करने की मांग स्वीकार नहीं की।

शेषन के समय सवाल था आयोग कितना ताकतवर है? यहीं दोनों सीईसी की कहानी का सबसे बड़ा अंतर

# फांसीसी छत्र आंदोलन की बढ़ती तपिश, 40 से अधिक शहर में लपटें?

#### शोभना जैन

फ्रांस में शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर अब तक का सबसे विशाल छत्र आंदोलन धीमा होने का नाम ही नहीं ले रहा है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में अव्यवस्था से क्षुब्ध स्कूली छात्रों, विश्वविद्यालयीन छात्रों के साथ अब श्रमिक यूनियन भी इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं। शिक्षा सुधारों को लेकर सितंबर में भड़का यह आंदोलन अब पूरे देश में फैलता जा रहा है।

देश के 40 से अधिक शहर इसकी लपटों में हैं। दरअसल छत्र स्कूलों में शिक्षा का बजट बढ़ाने की मांग करते हुए जर्जर इमारतों और शिक्षकों की कमी का विरोध कर रहे हैं। सरकार के कुछ सुधारात्मक कदम उठाने के संकेत के बावजूद दो दिन की अपेक्षाकृत मद्धम गति के बाद यह आंदोलन फिर और भड़क गया।

फ्रांस के शिक्षा मंत्रालय के अनुसार छत्र आंदोलन के अगले चरण से ठीक पहले देश के लगभग छह फीसदी मिडिल और हाईस्कूल आंदोलन के चलते बंद कर दिए गए हैं और लगभग 6000 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। दरअसल फ्रांस में स्कूली छात्रों की संख्या बढ़ने के अनुपात के मुकाबले स्कूलों में कक्षाएं, सुविधाएं और शिक्षकों की संख्या उसी अनुपात में नहीं बढ़ी हैं।

2008 की तुलना में माध्यमिक स्कूलों में अब शिक्षकों की संख्या कम है, जबकि छात्रों की संख्या करीब 2।5 लाख बढ़ गई है। इसी दबाव के चलते स्कूलों में भीड़ और सुविधाओं की कमी की शिकायतें बढ़ रही हैं।

फ्रांस में फिलहाल एक साथ कई मोर्चों पर संकट के बादल गहरा रहे हैं। विरोध सिर्फ स्कूलों तक सीमित नहीं है।

शिक्षक, सरकारी कर्मचारी, फायरफाइटर, स्वास्थ्यकर्मी और मछुआरे भी अलग-अलग मांगों



को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक माता-पिता और यूनियन कार्यकर्ताओं समेत बुजुर्ग, जवान सभी सफेद पट्टियां पहनकर जमा हुए हैं। देश के कुछ सबसे बड़े यूनियनों का गठबंधन भी उनके साथ शामिल हो गया है।

इसके साथ ही एक विचारधारा वाले राजनैतिक दल भी इसे समर्थन दे रहे हैं। सरकारी कर्मचारी सरकार के खर्च कम करने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें डर है कि बजट कटौती का असर उनकी सैलरी और दूसरी सुविधाओं पर पड़ेगा जबकि शिक्षक स्कूलों में शिक्षकों की कमी और काम के बढ़ते दबाव के साथ सरकार की बजट नीतियों का विरोध कर रहे हैं।

बहरहाल, फ्रांस में 90 के दशक में हुए कुछ बड़े छत्र आंदोलन के बाद मौजूदा आंदोलन सबसे विशाल और प्रभावी माना जा रहा है। स्थिति की गंभीरता को लेकर सरकार के अंदरखाने में क्या चल रहा है, इसे फ्रांस के शहर सेंट डेनिस के मेयर की इस टिप्पणी से समझा सकता है जिसमें उन्होंने कहा, ‘प्रदर्शनकारी मेरे बच्चे हो सकते हैं।’ उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार छात्रों की वाजिब मांगों पर जल्द ही नरमी से ठोस समाधान की राह पर आएगी।

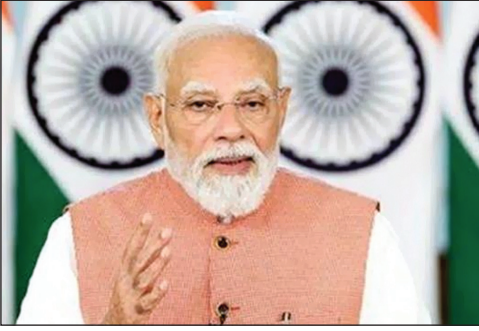
#### डा. सतीश पूनिया एवं सुनील बंसल

#### भारत के राजनीतिक इतिहास में कुछ ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं, जिनकी यात्रा केवल सत्ता के गलियारों तक सीमित नहीं रही, उन्होंने संगठन निर्माण, विचारधारा, जनसेवा और राि निर्माण की एक लंबी प्रक्रिया से गुजरते हुए अपनी राजनीतिक पहचान बनाई। नरेंद्र मोदी की राजनीतिक यात्रा को भी इसी व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। यह यात्रा एक ऐसे स्वयंसेवक की यात्रा है, जिसने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा से जनसेवा का संस्कार पाया, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में काम करते हुए अपनी पहचान बनाई, गुजरात का नेतृत्व किया और प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में स्वयं को स्थापित किया। 7 अक्टूबर, 2001 को नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। 2026 में वह सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस अवधि में लोगों के जीवन स्तर में सुधार और देश की प्रगति के लिए उनके निरंतर प्रयास और योगदान रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की कहानी 2001 से शुरू नहीं होती। इस लंबी यात्रा के पीछे दशकों का संगठनात्मक जीवन, अनुशासन और वैचारिक प्रशिक्षण रहा है।

आर.एस.एस. के स्वयंसेवक से देश के सेवक तक = नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन का विकास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ गहराई से जुड़ा रहा है। उनका संगठनात्मक जीवन अहमदाबाद से शुरू हुआ। बाद में उन्होंने प्रचारक के रूप में भी जिम्मेदारी निभाई। स्वयंसेवकों के जीवन में संगठन, अनुशासन, राि के प्रति प्रतिबद्धता और समाज के बीच लगातार काम करने पर जोर दिया जाता है। इसके बाद वह

भारतीय जनता पार्टी के संगठन में सक्रिय हुए। विभिन्न स्तरों पर संगठनात्मक जिम्मेदारियां निभाते हुए वे राष्ट्रीय राजनीति में आगे बढ़े। 7 अक्टूबर, 2001 को जब नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री का पद संभाला, तब राज्य एक कठिन दौर से गुजर रहा था। 2001 में कच्छ सहित गुजरात के बड़े हिस्से में विनाशकारी भूकंप आया था। इससे पहले सूखा और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी राज्य को प्रभावित कर चुकी थीं। उन्होंने गुजरात में सुशासन का ऐसा मॉडल विकसित करने का प्रयास किया, जिसमें बुनियादी ढांचे का निर्माण, निवेश, बिजली, कृषि, प्रशासनिक सुधार और समाज विकास प्राथमिकता बने। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मोदी ने 13 वर्ष तक जिम्मेदारी संभाली। यह उनके प्रशासनिक अनुभव की महत्वपूर्ण नींव बनी, जिसने बाद में उनकी राष्ट्रीय भूमिका को भी आकार दिया।

भाजपा नेता से प्रधानमंत्री तक = 2014 का लोकसभा चुनाव भारतीय राजनीति में एक निर्णायक मोड़ था। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को लोकसभा में पूर्ण बहुमत मिला। 26 मई, 2014 को उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। 2019 में भाजपा को एक बार फिर पूर्ण बहुमत



#### भारतीय जनता पार्टी के संगठन में सक्रिय हुए। विभिन्न स्तरों पर संगठनात्मक जिम्मेदारियां निभाते हुए वे राष्ट्रीय राजनीति में आगे बढ़े। 7 अक्टूबर, 2001 को जब नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री का पद संभाला, तब राज्य एक कठिन दौर से गुजर रहा था। 2001 में कच्छ सहित गुजरात के बड़े हिस्से में विनाशकारी भूकंप आया था। इससे पहले सूखा और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी राज्य को प्रभावित कर चुकी थीं। उन्होंने गुजरात में सुशासन का ऐसा मॉडल विकसित करने का प्रयास किया, जिसमें बुनियादी ढांचे का निर्माण, निवेश, बिजली, कृषि, प्रशासनिक सुधार और समाज विकास प्राथमिकता बने। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मोदी ने 13 वर्ष तक जिम्मेदारी संभाली। यह उनके प्रशासनिक अनुभव की महत्वपूर्ण नींव बनी, जिसने बाद में उनकी राष्ट्रीय भूमिका को भी आकार दिया।

यह शब्द उनकी राजनीतिक शैली का प्रतीक बन गया। इस शैली का मूल विचार है कि सत्ता कोई विशेषाधिकार नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का शासन बड़े पैमाने पर जनकल्याण और विकासोन्मुखी योजनाओं के लिए जाना जाता है। इनमें जनधन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जैसी योजनाएं शामिल हैं, जिनके माध्यम से लाखों लाभार्थियों तक पहुंचने का प्रयास किया गया। आवास, स्वच्छता, बैंकिंग, रसोई गैस, स्वास्थ्य सेवाओं और खड़ा सुरक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों को ध्यान में रखकर योजनाएं तैयार की गईं। इन कार्यक्रमों का मूल उद्देश्य गरीबों और समाज के कमजोर वर्गों तक बुनियादी सुविधाएं और आर्थिक अवसर पहुंचाना रहा है।

डिजिटल इंडिया-शासन की बदली हुई तस्वीर = मोदी युग की एक महत्वपूर्ण विशेषता भारत के सार्वजनिक जीवन का तेजी से डिजिटल होना है। डिजिटल भुगतान, यू.पी.आई., आधार आधारित सेवाएं, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे ने

सामने आता है। शेषन के दौर में सवाल था क्या चुनाव आयोग राजनीतिक दलों और सरकारों पर प्रभावी लगाम लगा सकता है? उन्होंने बूथ कैप्चरिंग, फर्जी मतदान, हिंसा, आचार संहिता के उल्लंघन और चुनावी अनियमितताओं पर कार्रवाई करके आयोग की ताकत दिखाई। आयोग अपनी इतनी बड़ी शक्ति का इस्तेमाल किस प्रक्रिया से कर रहा है? एसआईआर के जरिए मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर बदलाव, नए मतदाताओं से जुड़ी प्रक्रिया और आयोग के भीतर दर्ज आपत्तियों ने बहस को चुनावी अनुशासन से आगे बढ़ाकर पारदर्शिता, सामूहिक निर्णय और संस्थागत भरोसे तक पहुंचा दिया है। यही इस पूरी तुलना का सबसे दिलचस्प पहलू है। शेषन ने मुख्य चुनाव आयुक्त के पद को आम भारतीय की राजनीतिक शब्दावली में ला दिया। उन्होंने दिखाया कि संविधान में दर्ज शक्तियों का इस्तेमाल अगर सख्ती से किया जाए तो चुनावी व्यवस्था के तौर-तरीके बदले जा सकते हैं।

ज्ञानेश कुमार के दौर में वही पद फिर चर्चा में है, लेकिन चर्चा का केंद्र एसआईआर, मतदाता सूची और आयोग की निर्णय प्रक्रिया है। इसलिए सवाल शेषन बनाम ज्ञानेश का नहीं, उस पद की बदलती भूमिका का है। शेषन ने सीईसी की ताकत दिखाई थी; ज्ञानेश कुमार के दौर ने उसी ताकत के इस्तेमाल की प्रक्रिया और पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तीन दशक पहले बहस थी सीईसी कितना ताकतवर हो सकता है? आज बहस है उस ताकत का इस्तेमाल कैसे हो रहा है और उस पर भरोसा कैसे कायम रहेगा? यही फर्क टीएन शेषन और ज्ञानेश कुमार को एक साथ चर्चा में लाता है एक ने चुनाव आयोग को ताकत का चेहरा बनाया, दूसरे के दौर में चुनाव आयोग की ताकत ही बहस का विषय बन गई।

## 25 वर्ष : लक्ष्य से आगे की एक कहानी

#### मिला। 2024 में नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इस यात्रा का एक विशेष रूप से उल्लेखनीय पक्ष यह है कि एक सामान्य संगठनात्मक कार्यकर्ता देश के सर्वोच्च निर्वाचित प्रशासनिक पद तक पहुंचा। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी ने अपने साथ ‘प्रधान सेवक’ की अवधारणा को जोड़ा। उनके समर्थकों के लिए

नागरिकों और सरकार के बीच संवाद और सेवाओं के स्वरूप को बदल दिया है। भारत की डिजिटल क्षमता को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी महत्व मिला। 2023 में भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, ग्लोबल साइथ और समावेशी विकास पर विशेष जोर दिया गया।

विश्व मंच पर नया भारत = पिछले एक दशक में विश्व मंच पर भारत की भूमिका नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की एक महत्वपूर्ण पहचान बनी है। ब्राह्म, जी20, ग्लोबल साइथ, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और अन्य बहुपक्षीय मंचों पर भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मोदी की विदेश नीति का एक प्रमुख संदेश यह रहा है कि भारत विश्व व्यवस्था में केवल एक सहभागी के रूप में नहीं रहेगा, बल्कि प्रभाव पैदा करने में सक्षम एक मजबूत राष्ट्र की भूमिका निभाएगा।

स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी का योगदान = किसी भी नेतृत्व का वास्तविक योगदान समय की कसौटी पर परखा जाता है। उसके निर्णयों के स्थायी परिणाम, संस्थाओं पर प्रभाव, नागरिक जीवन में एक बदलाव और भावी पीढ़ियों पर उसके असर से उसका मूल्यांकन होता है। इस अर्थ में नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष स्वतंत्र भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय हैं। यदि उनके 25 वर्षों की इस यात्रा को एक वाक्य में लिखा जाए, तो कहा जा सकता है कि यह सत्ता की यात्रा से अधिक जिम्मेदारी की यात्रा है। पद की यात्रा से अधिक सेवा की यात्रा है। यह केवल एक व्यक्ति की यात्रा नहीं, बल्कि एक विचार और भारत के उस संकल्प की यात्रा है, जिसे वह ‘विकसित भारत’ के रूप में देखना चाहते हैं।

## चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता व जनभागीदारी जरूरी

#### रविंदर नरना

किसी चुनावी प्रणाली की अखंडता केवल चुनावों के संचालन पर ही नहीं, बल्कि उन प्रक्रियाओं की सार्वजनिक समझ पर भी निर्भर करती है जिनके माध्यम से मतदाता सूचियां तैयार, संशोधित और अंतिम रूप दी जाती हैं। विशेष सघन पुनरीक्षण एस.आई.आर. को लेकर हाल ही में हुई सार्वजनिक बहस ने ड्राफ्ट-चरण की जानकारी और अंतिम मतदाता-सूची के आंकड़ों के बीच अंतर करने के महत्व को उजागर किया है। व्यापक रूप से प्रसारित एक दावे में ‘13 करोड़ मतदाताओं के हटाए जाने’ का उल्लेख है। चुनाव आयोग की आपूर्ति की गई सामग्री के अनुसार, यह आंकड़ा विभिन्न श्रेणियों में आने वाली ड्राफ्ट-चरण की प्रविष्टियों से संबंधित है, जिसमें लगभग 2.8 करोड़ मृत, 3 करोड़ अनुपस्थित। पता न चलने वाले, 6.3 करोड़ स्थायी रूप से स्थानांतरित और 1 करोड़ दोहरे नामांकन शामिल हैं। ये श्रेणियां 13 करोड़ अंतिम विलोपन के समतुल्य नहीं हैं। मतदाता-सूची की प्रक्रिया सत्यपन, दावों और आपत्तियों तथा अंतिम रूप दिए जाने के दौर से गुजरती है, जिसके बाद अंतिम सूची तैयार की जाती है। भारत का चुनावी इतिहास वह प्रदर्शित करता है कि संस्थागत विश्वसनीयता समय के साथ निर्मित हुई है। 1990 के दशक में टी.एन. शेषन का कार्यकाल आयोग की मौजूदा शक्तियों के अधिक मुख्र प्रयोग के लिए याद किया जाता है, जिसमें आचार संहिता का सख्ती से अमल और आयोग की भूमिका की अधिक दृश्यता शामिल है। उस दौर का महत्व केवल यह नहीं था कि आयोग ने शक्ति का प्रयोग किया, बल्कि यह था कि नागरिक उसे राजनीतिक दबावों से स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम संस्था के रूप में तेजी से देखने लगे। तीन दशक बाद, चुनौती का स्वरूप भिन्न है। आयोग ऐसे सूचना परिवेश में काम करता है जहां कोई दावा उसकी प्रासंगिकता समझे जाने से पहले ही लाखों

स्क्रीन पर यात्रा कर सकता है। चुनावी डेटा, प्रशासनिक निर्णय और तकनीकी प्रक्रियाएं एक शीर्षक या एक छोटे वीडियो तक सीमित की जा सकती हैं। ऐसे परिवेश में, संस्थागत संचार चुनावी पारदर्शिता का हिस्सा बन जाता है। मतदाता-सूची पुनरीक्षण पर हालिया बहस इस बिंदू को स्पष्ट करती है। ड्राफ्ट अध्यास से जुड़े एक बड़े आंकड़े को ऐसा अर्थ मिल सकता है जो उसकी वास्तविक प्रशासनिक स्थिति से काफी भिन्न हो। आयोग का अपना चुनावी ढांचा समावेशन के लिए दावों, प्रस्तावित समावेशन या विलोपन पर आपत्तियों और निवास के सुधार या स्थानांतरण के आवेदनों के बीच अंतर करता है। इसलिए, सार्वजनिक संदेह का उत्तर केवल यह नहीं हो सकता कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक प्राधिकारी है। संवैधानिक दर्जा आयोग के जनादेश की स्थापित करता है जब उस जनादेश का प्रयोग पारदर्शिता के साथ किया जाता है और उसके निर्णय समझते तथा जांचने योग्य होते हैं, तब जनविश्वास मजबूत होता है। इसके लिए आयोग से हर आलोचक को संतुष्ट करने की अपेक्षा नहीं की जाती। कोई भी स्वतंत्र संवैधानिक संस्थान सार्वभौमिक सहमति की मांग करके कार्य नहीं कर सकता। हालांकि, इसके लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी प्रक्रियाओं को स्पष्ट रूप से समझाए, प्रासंगिक जानकारी सुलभ रूपों में प्रकाशित करे और अंनतिम जानकारी, प्रशासनिक निर्णयों तथा अंतिम परिणामों के बीच अंतर बताएं। यही सिद्धांत गलतियों पर भी लागू होता है। भारत के पैमाने का चुनावी प्रक्रिया का संचालन करने वाला संस्थान अपरिहार्य रूप से त्रुटियों, चुकों और विवादों का सामना करेगा। संस्थागत विश्वसनीयता के लिए यह दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसी समस्याएं उत्पन्न नहीं हो सकतीं। इसके लिए यह प्रदर्शित करने की आवश्यकता है कि स्थापित प्रक्रियाओं के माध्यम से त्रुटियों की पहचान की जा सकती है, उन्हें सुधारा जा सकता है और उनका हिसाब रखा जा सकता है।

## विरोध, अत्यवस्था और पुलिस का कठिन कर्त्तव्य !

#### रजनीश कपूर

लोकतंत्र केवल मतपेटी में बंद मतों का नाम नहीं है। वह उस सांस का भी नाम है, जिसमें नागरिक अपनी नाराजगी शांतिपूर्वक सड़क पर रख सके। भारत के संविधान ने यह सांस अनुच्छेद 19(1)(क) और 19(1)(ख) में दी है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और बिना हथियार के शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार और सीमा भी उसी अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 19(2) और 19(3) संप्रभुता, अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था के हित में युक्तियुक्त निर्बंधन की अनुमति देते हैं। यहीं से पुलिस का कठिन कर्तव्य शुरू होता है। उसे न विरोध को कुचलना है, न अव्यवस्था को खुली छूट देनी है।

यह इंद्र किसी एक आंदोलन की संपत्ति नहीं है। परीक्षा-पत्र लीक से निकले युवा मार्च हों, किसान कानूनों के खिलाफ घेराव हो, नागरिकता कानून पर धरना हो, या चुनावी सूची और निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता पर उठे सवाल हों, हर बार सवाल एक ही लौटता है। राज्य विरोध को सुविधा दे रहा है या केवल उसे नियंत्रित करने के नाम पर संकुचित कर रहा है। अक्टूबर 2026 का दिल्ली दृश्य इसी प्रश्न की ताजा तस्वीर है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और विशेष गहन पुनरीक्षण (एस.आई.आर.) पर विपक्षी गठबंधन के सांसद जंतर-मंतर की ओर बढ़े, तो लुटियंस दिल्ली बैरिकेड, आर.ए.एफ. और केंद्रीय बलों की छावनी बन गई। बसें रोक दी गईं, रास्ते सील कर दिए गए।

उसी बीच, पेपर लीक मुद्दे पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेने वाली कॉन्ग्रेस जनता पार्टी ने 10 अक्टूबर के जंतर-मंतर प्रदर्शन की औपचारिक सूचना संसद मार्ग थाने में दी। पिछली बार के धरने से सबक लेते हुए इस बार दिल्ली पुलिस ने अनुमति नामंजूर कर दी। तर्क यह था कि निर्धारित स्थल पर भी बैठक या धरने के लिए आवेदन कम से कम 10 दिन पहले देना होता है और भीड़ के आकार के अनुसार स्थल जंतर-मंतर, रामलीला मैदान या बुराड़ी तय होते हैं। कानून इस बहस में खाली नहीं है। भारतीय



नागरिक सुरक्षा संहिता की वे धाराएं, जो पहले दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 129 से 132 थीं, कार्यपालक मजिस्ट्रेट या थाना प्रभारी को गैरकानूनी जमाव को तितर-बितर करने का आदेश देती हैं। बल तभी है जब आदेश न माना जाए और तब भी जितना कम बल और जितनी कम क्षति हो, उतना ही। धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लगाई जा सकती है, पर सर्वोच्च न्यायालय अनुराधा भसीन मामले में कह चुका है कि ऐसा आदेश वास्तविक आपात पर टिका हो, तथ्यों को दर्ज करे और अनुपातिकता की कसौटी पर खरा उतरे। हिम्मत लाल शाह (1973) केस में सार्वजनिक सड़कों पर बैठकों का पूर्ण निषेध नकारा गया। रामलीला मैदान (2012) में प्रक्रियात्मक सुरक्षा को औपचारिकता नहीं माना गया।

अमित साहनी, यानी शाहीन बाग (2020) में शांतिपूर्ण विरोध को माना गया, पर सार्वजनिक मार्ग के अनिश्चितकालीन कब्जे को नहीं। मार्च 2025 में न्यायालय ने कहा कि पुलिस अनुच्छेद 12 के अर्थ में राज्य का अंग है, इसलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा उसका संवैधानिक दायित्व है। जुलाई 2026 में, नीट व अन्य पेपर लीक पर ‘चलो संसद’ मार्च के बाद, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने मौखिक रूप से रेखांकित किया कि शांतिपूर्ण विरोध गारंटीकृत है और केवल आंदोलन होने से लाठीचार्ज जायज नहीं हो जाता। जुलाई का वह मार्च याद दिलाने लायक है, क्योंकि वहां बल की सीमा ही विवाद बनी। पुलिस का पक्ष था कि मार्च माना था, भीड़ ने बैरिकेड

तोड़े और पथराव किया, बल अंतिम उपाय था और इस प्रदर्शन में 100 से अधिक सुरक्षाकर्मी घायल हुए। प्रदर्शनकारियों, अस्पताल रिकॉर्ड और बाद की रिपोर्टों ने लाठी, आंसू गैस और पैलेट गन के इस्तेमाल की बात कही। न्यायालय ने नाबालिगों की रिहाई के आदेश दिए और स्वतंत्र जांच का पैनल बनाया। वहीं दिल्ली पुलिस ने अपने आचरण को कानूनी और पेशेवर बताया।

इसी ढांचे में वर्दी की नैतिक स्थिति समझी जा सकती है। धरने प्रदर्शन का सामना कर रहा पुलिस का सिपाही अक्सर उसी वर्ग से आता है, जिससे प्रदर्शनकारी। वह परीक्षा की अनियमितता, बेरोजगारी, फसल के दाम या मतदाता सूची के संदेह को व्यक्तिगत रूप से समझ सकता है। पर उसके साथ ही वर्दी में वह राजनीतिक कार्यपालिका के आदेश का सेवक है। स्थानांतरण, पदोन्नति और विभागीय जांच उसी सत्ता के हाथ में हैं, जिसकी नीतियों के खिलाफ भीड़ खड़ी होती है। परिणाम यह होता है कि ‘न्यूनतम बल’ का सिद्धांत असल में मौके पर ‘आदेश का पालन’ में सिकुड़ जाता है।

यह भी सच है कि जब भीड़ पथराव करती है, वाहन क्षतिग्रस्त करती है या सुरक्षाकर्मियों पर हमला होता है, तब संयम बरतने वाले अधिकारी को बाद में ढिलाई का आरोप झेलना पड़ता है। पुलिस न पूरी तरह दमन का औजार है, न भीड़ की स्वयंसेवक। वह बीच की संस्था है। उसकी निष्पक्षता तभी बचती है जब राजनीतिक आका ऐसा कोई आदेश दें, पर कानून सीमा बांधे। सुधार किसी एक प्रदर्शन को जीत-हार से नहीं निकलेगा। बल प्रयोग की हर घटना की वीडियो, समय और आदेश-शृंखला सार्वजनिक होनी चाहिए। निषेधाज्ञा लिखित हो और बाद में अनुपातिकता की स्वतंत्र जांच हो। प्रदर्शनकारियों के लिए भी सीमा साफ है। बिना हथियार, बिना मार्ग के अन्त कब्जे और बिना इश्वहा के। लोकतंत्र में पुलिस संविधान का अधिकर्ता है। जब वह राजनीतिक इच्छा और नागरिक के नैतिक दावे के बीच कानून को चुनती है, तभी विरोध सड़क की गरमी बना रहता है, राजधानी का घेरा नहीं।

वर्ष के चार नवरात्रों में चैत्र, आषाढ़, आश्विन और माघ की शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक नौ दिन के होते हैं, परंतु प्रसिद्धि में चैत्र और आश्विन के नवरात्र ही मुख्य माने जाते हैं। नवरात्र में देवी माँ के व्रत रखे जाते हैं। स्थान-स्थान पर देवी माँ की मूर्तियाँ बनाकर उनकी विशेष पूजा की जाती है। मान्यता है कि नवरात्र में महाशक्ति की पूजा कर श्रीराम ने अपनी खोई हुई शक्ति पाई, इसलिए इस समय आदिशक्ति की आराधना पर विशेष बल दिया गया है।

# ऊर्जा का उत्सव नवरात्री



नवरात्रि एक हिंदू पर्व है। नवरात्रि संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ होता है नौ रातें। यह पर्व साल में चार बार आता है। चैत्र, आषाढ़, अश्विन, पोषप्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। नवरात्रि के नौ रातों में तीन देवियों – महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वतीया सरस्वतीकि तथा दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा होती है जिन्हे नवदुर्गा कहते हैं। नौ देवियाँ है – श्री शैलपुत्री, श्री ब्रह्मचारिणी, श्री चंद्रघंटा, श्री कुष्मांडा, श्री स्कंदमाता, श्री कात्यायनी, श्री कालरात्रि, श्री महागौरी, श्री सिद्धिदात्री। शक्ति की उपासना का पर्व शारदेय नवरात्र प्रतिपदा से नवमी तक निश्चित नौ तिथि, नौ नक्षत्र, नौ शक्तियों की नवधा भक्ति के साथ सनातन काल से मनाया जा रहा है। सर्वप्रथम श्रीरामचंद्रजी ने इस शारदीय नवरात्रि पूजा का प्रारंभ समुद्र तट पर किया था और उसके बाद दसवें दिन लंका विजय के लिए प्रस्थान किया और विजय प्राप्त की। तब से असत्य, अधर्म पर सत्य, धर्म की जीत का पर्व दशहरा मनाया जाने लगा। आदिशक्ति के हर रूप की नवरात्र के नौ दिनों में क्रमशः अलग-अलग पूजा की जाती है। माँ दुर्गा की नौवी शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियाँ देने वाली हैं। इनका वाहन सिंह है और कमल पुष्प पर ही आसीन होती हैं । नवरात्रि के नौवें दिन इनकी उपासना की जाती है। नवदुर्गा और दस महविधाओं में काली ही प्रथम प्रमुख हैं। भगवान शिव की शक्तियों में उग्र और सौम्य, दो रूपों में अनेक रूप धारण करने वाली दस महाविधाएँ अनंत सिद्धियाँ प्रदान करने में समर्थ हैं। दसवें स्थान पर कमला वैष्णवी शक्ति हैं, जो प्राकृतिक संपत्तियों की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी हैं। देवता, मानव, दानव सभी इनकी कृपा के बिना पंगु हैं, इसलिए आगम-निगम दोनों में इनकी उपासना समान रूप से वर्णित है। सभी देवता, राक्षस, मनुष्य, गंधर्व इनकी कृपा-प्रसाद के लिए लालायित रहते हैं।

### प्रमुख कथा

लंका-युद्ध में ब्रह्माजी ने श्रीराम से रावण वध के लिए चंडी देवी का पूजन कर देवी को प्रसन्न करने को कहा और बताए अनुसार चंडी पूजन और हवन हेतु दुर्लभ एक रसी आठ नीलकमल की व्यवस्था की गई। वहीं दूसरी ओर रावण ने भी अमरता के लोभ में विजय कामना से चंडी पाठ प्रारंभ किया। यह बात इंद्र देव ने पवन देव के माध्यम से श्रीराम के

पास पहुँचाई और परामर्श दिया कि चंडी पाठ यथासंभव पूर्ण होने दिया जाए। इधर हवन सामग्री में पूजा स्थल से एक नीलकमल रावण की मायावी शक्ति से गायब हो गया और राम का संकल्प टूटता-सा नजर आने लगा। भय इस बात का था कि देवी माँ रुष्ट न हो जाएँ। दुर्लभ नीलकमल की व्यवस्था तत्काल असंभव थी, तब भगवान राम को सहज ही स्मरण हुआ कि मुझे लोग कमलनयन नवकंच लोचन कहते हैं, तो क्यों न संकल्प पूर्ति हेतु एक नेत्र अर्पित कर दिया जाए और प्रभु राम जैसे ही तृणीर से एक बाण निकालकर अपना नेत्र निकालने के लिए तैयार हुए, तब देवी ने प्रकट हो, हाथ पकड़कर कहा- राम मैं प्रसन्न हूँ और विजयश्री का आशीर्वाद दिया। वही रावण के चंडी पाठ में यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों की सेवा में ब्राह्मण बालक का रूप धर कर हनुमानजी सेवा में जुट गए। निःस्वाथ सेवा देखकर ब्राह्मणों ने हनुमानजी से वर माँगने को कहा। इस पर हनुमान ने विनम्रतापूर्वक कहा- प्रभु, आप प्रसन्न हैं तो जिस मंत्र से यज्ञ कर रहे हैं, उसका एक अक्षर मेरे कहने से बदल दीजिए। ब्राह्मण इस रहस्य को समझ नहीं सके और तथास्तु कह दिया। मंत्र में जयादेवी... भूर्तिहरिणी में ह के स्थान पर क उच्चारित करें, यही मेरी इच्छा है। भूर्तिहरिणी यानी कि प्राणियों की पीड़ा हरने वाली और करिणी का अर्थ हो गया प्राणियों को पीड़ित करने वाली, जिससे देवी रुष्ट हो गई और रावण का सर्वनाश करवा दिया। हनुमानजी महाराज ने श्लोक में ह की जगह क करवाकर रावण के यज्ञ की दिशा ही बदल दी।

### अन्य कथाएं

इस पर्व से जुड़ी एक अन्य कथा अनुसार देवी दुर्गा ने एक भैंस रूपी असुर अर्थात महिषासुर का वध किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर के एकाग्र ध्यान से बाध्य होकर देवताओं ने उसे अजय होने का वरदान दे दिया। उसको वरदान देने के बाद देवताओं को चिंता हुई कि वह अब अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करेगा। और प्रत्याशित प्रतिफल स्वरूप महिषासुर ने नरक का विस्तार स्वर्ग के द्वार तक कर दिया और उसके इस कृत्य को देख देवता विस्मय की स्थिति में आ गए। महिषासुर ने सूर्य, इन्द्र, अग्नि, वायु, चन्द्रमा, यम, वरुण और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और स्वयं स्वर्गलोक का मालिक बन बैठा। देवताओं को महिषासुर के प्रकोप से पृथ्वी पर विचरण करना पड़ रहा है। तब महिषासुर के इस दुस्साहस से क्रोधित होकर देवताओं ने देवी दुर्गा की रचना की। ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा के निर्माण में सारे देवताओं का एक समान बल लगाया गया था। महिषासुर का नाश करने के लिए सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र देवी दुर्गा को दिए थे और कहा जाता है कि इन देवताओं के सम्मिलित प्रयास से देवी दुर्गा और बलवान हो गई थी। इन नौ दिन देवी-महिषासुर संग्राम हुआ और अन्ततः महिषासुर-वध कर महिषासुर मर्दिनी कहलायी।

### निर्माणाधीन मूर्तियां

चौमासे में जो कार्य स्थगित किए गए होते हैं, उनके आरंभ के लिए साधन इसी दिन से जुटाए जाते हैं। क्षत्रियों का यह बहुत बड़ा पर्व है। इस दिन ब्राह्मण सरस्वती-पूजन तथा क्षत्रिय शस्त्र-पूजन आरंभ करते हैं। विजयदशमी या दशहरा एक राष्ट्रीय पर्व है। अर्थात आश्विन शुक्ल दशमी को सायंकाल तारा उदय होने के समय विजयकाल रहता है। यह सभी कार्यों को सिद्ध करता है। आश्विन शुक्ल दशमी पूर्वविद्धा निषिद्ध, परविद्धा शुद्ध और श्रवण नक्षत्रयुक्त सुयोदयव्यापिनी सर्वश्रेष्ठ होती है। अपराह्न काल, श्रवण नक्षत्र तथा दशमी का प्रारंभ विजय यात्रा को मुहूर्त माना गया है। दुर्गा-विसर्जन, अपराजिता पूजन, विजय-प्रयाग, शमी पूजन तथा नवरात्र-पारण इस पर्व के महान कर्म हैं। इस दिन संध्या के समय नीलकंठ पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है। क्षत्रिय/राजपूतों इस दिन प्रातः स्नानादि नित्य कर्म से निवृत्त होकर संकल्प मंत्र लेते हैं। इसके पश्चात देवताओं, गुरुजन, अस्त्र-शस्त्र, अश्व आदि के यथाविधि पूजन की परंपरा है।

चौथे दिन इन्हें वस्त्र देने का महत्व है लेकिन सामर्थ्य अनुसार रुमाल या रंगबिरंगे रीबन दिए जा सकते हैं।

- पांचवे दिन देवी से सौभाग्य और संतान प्राप्ति की मनोकामना की जाती है। अतः कन्याओं को पांच प्रकार की श्रृंगार सामग्री देना अत्यंत शुभ होता है। इनमें बिंदिया, चूड़ी, मेहंदी, बालों के लिए विलस, सुगंधित साबुन, काजल, नैलपॉलिश, टैल्कम पावडर इत्यादि हो सकते हैं।
- छठे दिन बच्चियों को खेल-सामग्री देना चाहिए। आजकल बाजार में खेल सामग्री की अनेक वैरायटी उपलब्ध है। पहले यह रिवाज पांचे, रस्सी और छोटे-मोटे खिलौनों तक सीमित था। अब तो ढेर सारे विकल्प मौजूद हैं।
- सातवां दिन मां सरस्वती के आह्वान का होता है। अतः इस दिन कन्याओं को शिक्षण सामग्री दी जानी चाहिए। आजकल स्टेशनरी बाजार में विभिन्न प्रकार के पेन, स्कैच पेन, पेंसिल, कॉपी, ड्रॉइंग बुक्स, कपास, वाटर बॉटल, कलर बॉक्स, लंच बॉक्स उपलब्ध है।
  - आठवां दिन नवरात्रि का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन अगर कन्या का अपने हाथों से श्रृंगार किया जाए तो देवी विशेष आशीर्वाद देती है। इस दिन कन्या के दूध से पैर पूजने चाहिए। पैरों पर अक्षत, फूल और कुंकुम लगाना चाहिए। इस दिन कन्या को भोजन कराना चाहिए और यथासामर्थ्य कोई भी भेट देनी चाहिए। हर दिन कन्या-पूजन में दक्षिणा अवश्य दें।
    - नौवें दिन खीर, ग्वारफली और दूध में गुंथी पुरियां कन्या को खिलानी चाहिए। उसके पैरों में महावर और हाथों में मेहंदी लगाने से देवी पूजा संपूर्ण होती है। अगर आपने घर पर हवन का अयोजन किया है तो उसके नन्हे हाथों से उसमें समिधा अवश्य डलवाए। उसे इलायची और पान का सेवन कराए।

दिल में कोई भौतिक कामना है तो लाल पुष्प देकर इन्हें खुश करें। (उदाहरण के लिए - गुलाब, चंपा, मोगरा, गेंदा, गुड़हल)

- दूसरे दिन फल देकर इनका पूजन करें। यह फल भी सांसारिक कामना के लिए लाल अथवा पीला और वैराग्य की प्राप्ति के लिए केला या श्रीफल हो सकता है। याद रखें कि फल खट्टे ना हो।
- तीसरे दिन मिठाई का महत्व होता है। इस दिन अगर हाथ की बनी खीर, हलवा या केशरिया चावल बना कर खिलाए जाएं तो देवी प्रसन्न होती है।



प्रथम दिन इन्हें फूल की भेंट देना शुभ होता है। साथ में कोई एक श्रृंगार सामग्री अवश्य दें। अगर आप मां सरस्वती को प्रसन्न करना चाहते है तो श्वेत फूल अर्पित करें। अ ग र आप के



## कैसे करें घट स्थापना

आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शारदीय नवरात्रि की धूम नौ दिनों तक रहेगी। इन दिनों मां भगवती के नौ रूपों का पूजन-अर्चन होगा। आइए जानते हैं घटस्थापना कैसे करें –

- घटस्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए।
- नित्य कर्म और स्नान के बाद ध्यान करें।
- इसके बाद पूजन स्थल से अलग एक पाटे पर लाल व सफेद कपड़ा बिछाएं।
- इस पर अक्षत से अष्टदल बनाकर इस पर जल से भरा कलश स्थापित करें।
- इस कलश में शतावरी जड़ी, हलकुंड, कमल गृष्ट व रजत का सिका डालें।
- दीप प्रज्वलित कर इष्ट देव का ध्यान करें।
- तत्पश्चात देवी मंत्र का जाप करें।
- अब कलश के सामने गेहूं व जौ को मिट्टी के पात्र में रोपें।
- इस ज्वारे को माताजी का स्वरूप मानकर पूजन करें।
- अंतिम दिन ज्वारे का विसर्जन करें।



## नवरात्रि के चमत्कारिक दिव्य मंत्र

वर्तमान में मनुष्य ने अपने जीवन को इतनी आवश्यकताओं से घेर लिया है कि वह उनमें ही उलझा रहता है। ऐसे मनुष्यों के लिए समस्याओं को हल करने के लिए सरलतम मंत्र दे रहे हैं। जो नवरात्रि में करने से सफलता मिलती है एवं समस्या से छुटकारा मिलता है। ऐसे पावन नौ दिनों के लिए दिव्य मंत्र दिए जा रहे हैं, जिनके विधिवत परायण करने से स्वयं के नाना प्रकार के कार्य व सामूहिक रूप से दूसरों के कार्य पूर्ण होते हैं। इन मंत्रों को नौ दिनों में अवश्य जाप करें। इनसे यश, सुख, समृद्धि, पराक्रम, वैभव, बुद्धि, ज्ञान, सेहत, आयु, विद्या, धन, संपत्ति, ऐश्वर्य सभी की प्राप्ति होती है। विपत्तियों का नाश होगा।

#### विपत्ति-नाश के लिए

शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे।
सर्वस्पापहरे देवि नारायणि नमोस्तुते।।

#### भय नाश के लिए

सर्वस्वरूपे सर्वशः सर्वशक्तिसमन्विते।
भयेभ्यस्त्राहि नो देवि, दुर्गे देवि नमोस्तुते।।

#### पाप नाश तथा

#### भक्ति की प्राप्ति के लिए

नमेश्य सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि क्षिपो जहि।।

#### हर प्रकार के कल्याण के लिए

सर्वमंगल्यमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके।
शरण्ये त्व्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते।।

#### धन, पुत्रादि प्राप्ति के लिए

सर्वबाधाविनिर्मुक्तो-धनधान्यसुतान्वित
मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशय।।



#### रक्षा पाने के लिए

शूलेन पाहि नो देवि पाहि खंडे न चाम्बिके।
घण्टास्वनेन न पाहि चापज्यानि स्वनेन च।।

#### मोक्ष की प्राप्ति के लिए

त्वं वैष्णवी शक्तिरन्तर्वीर्या।
विश्वस्य बीजं परमासि माया।
सम्मोहितं देवि समस्तमेत
त्वं वै प्रसन्ना भूवि मुक्ति हेतु।।

#### बाधा व शांति के लिए

सर्वबाधाप्रमशन त्रैलोक्याखिलेश्वर।
एवमेव त्वया कार्यमस्यद्दैरिनिनाशनम्।।

#### सुलक्षणा पत्नी की प्राप्ति के लिए

पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीम
तारिणी दुर्गसंसारसागरस्य कुलोद्भवाम।।

### दिल्ली को किले में बदलने पर भड़के शशि थरूर



**नई दिल्ली।** कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने दिल्ली में काँकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन को लेकर लगाई गई पारबंदियों की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि चुनाव की निष्पक्षता को लेकर सवाल पूछने वालों का जवाब देने के बजाय सरकार राजधानी को किले में बदल रही है। इससे लोगों का संदेह दूर होने के बजाय और बढ़ेगा। थरूर ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि जिस सरकार को अपने चुनावों की निष्पक्षता पर भरोसा है, उसे सवालों का स्वागत करना चाहिए। थरूर ने कहा, सरकार को जवाब देने चाहिए, लाटियां नहीं; अभिव्यक्ति की आजादी देनी चाहिए, दमन नहीं। बैरिकेड लगाने से चुनाव आयोग पर लोगों का भरोसा बहाल नहीं होगा। जनता के सवालों के जवाब जितनी जल्दी दिए जाएंगे, शांति उतनी ही जल्दी लौटेगी। शशि थरूर ने कहा कि वह रात दो बजे के बाद राष्ट्रीय राजधानी लौटे और दिल्ली में इस तरह की सख्ती पहले शायद ही कभी देखी हो।

### चेन्नई में राहुल गांधी के दौरे को लेकर पांच स्तरीय सुरक्षा



**नईदिल्ली।** कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ‘छात्रों की गुंज’ कार्यक्रम और मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के साथ दोपहर के भोजन पर मुलाकात के लिए चेन्नई पहुंचने के मद्देनजर शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के रविवार को यहां कई कार्यक्रमों में शामिल होने के कारण भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ‘छात्रों की गुंज’ कार्यक्रम में प्रवेश केवल क्यूआर कोड के जरिए दिया जाएगा। इसके लिए पुरुषों और महिलाओं के प्रवेश के अलग-अलग गलियारों बनाए गए हैं, जबकि आम जनता को कार्यक्रम स्थल से दूर रखा गया है। चेन्नई पुलिस आयुक्त ए. अमलराज के नेतृत्व में शहर में 15,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ पांच स्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के तहत कार्यक्रम स्थल और अति वशिष्ट व्यक्तियों के आवागमन वाले मार्गों पर निगरानी रखी जा रही है।

### युवाओं को रोकना सरकार की बड़ी मूल साबित होगी : अखिलेश



**लखनऊ।** समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने काँकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के विरोध-प्रदर्शन के बीच दिल्ली को किले में बदलने के कदम की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार का यह कदम एक बड़ी गलती साबित होगा। अखिलेश ने कहा कि अगर सरकार युवाओं को रोकने की कोशिश करती है, तो पूरा देश दिल्ली में इकट्ठा हो जाएगा। सीजेपी के आंदोलन का समर्थन करते हुए अखिलेश ने कहा कि वह और उनकी पार्टी देश के युवाओं की ऊर्जा और जज्बे के साथ खड़े हैं। अखिलेश ने एक्स पर हिंदी में एक पोस्ट में कहा कि अब पूरा देश दिल्ली में इकट्ठा होगा! उन्होंने आगे कहा कि अगर भाजपा सरकार को लगता है कि वह ताकत के इस्तेमाल से लोगों को रोक सकती हैं, तो यह और भी बड़ी गलती साबित होगी। जंतर-मंतर अब सिर्फ एक जगह का नाम नहीं रह गया है; यह नई चेतना और जागृति का प्रतीक बन गया है।

### असहमति जताना कोई अपराध नहीं : एमके स्टालिन



**चेन्नई।** दिल्ली के जंतर-मंतर पर काँकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से पहले, डीएमके अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने शनिवार को कहा कि असहमति जताना कोई अपराध नहीं है और लोकतंत्र उन लोगों की आवाज दबाकर जंदा नहीं रह सकता। जो इसकी रक्षा के लिए आगे आते हैं। एमके स्टालिन ने एक्स पर कहा, आज दिल्ली में जो हो रहा है और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर जिस तरह से दमन किया जा रहा है। उससे मुझे इमरजेंसी के वे दर्दनाक दिन याद आ गए, जिन्हें मैंने खुद देखा था। दिल्ली और देश भर में हिरासत में लिए गए सभी राजनीतिक नेताओं, छात्रों और युवा प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, मैं तमिलनाडु में टीवीके सरकार को कड़ी नंिंद करता हूं क्योंकि वह भाजपा के विस्तार के तौर पर काम कर रही है। इसके साथ ही विरोध कर रहे छात्रों पर पुलिस का दमन ढा रही है। केंद्र सरकार को उन युवाओं के खिलाफ कार्रवाई तुरंत बंद करनी चाहिए।

### 6 महीने के अंदर गिर जाएगी मोदी सरकार : संजय राउत



**मुंबई।** सांसद संजय राउत ने तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ सनसनीखेज दावे किए हैं। ठाकरे गुट के सांसद राउत ने देश में बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल की भविष्यवाणी की है और दावा किया है कि मोदी सरकार अगले छह महीनों में गिर जाएगी। दिल्ली में हो रहे विरोध-प्रदर्शनों के बीच उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों पर तीखा हमला बोला। वे पुणे में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने दिल्ली को जम्मू-कश्मीर बना दिया है। दिल्ली की सभी सीमाएं बंद कर दी गई हैं, सड़कें सील कर दी गई हैं और उड़ानें व ट्रेनें रोक दी गई हैं। उन्होंने नाराजगी जताते हुए पूछा कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आतंकवादियों से लड़ने की बात करते हैं; तो जब देश के युवा लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करते हैं, तो क्या उन्हें आतंकवादी करार दिया जा रहा है? इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने भविष्यवाणी की कि अप्रैल में सरकार गिर जाएगी और देश में एक वैकल्पिक सरकार बनेगी। उन्होंने पुलिस से यह भी कहा कि वे किसी भी गैर-कानूनी आदेश का पालन न करें।

# चुनावी हार से हताश होकर देश को अस्थिर कर रहे राहुल गांधी : नितिन नवीन

**नईदिल्ली।** दिल्ली के जंतर-मंतर पर काँकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को लेकर बढ़ते तनाव के बीच, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्षी दलों पर विदेशी ताकतों के प्रभाव में देश को अस्थिर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। नितिन नवीन ने कहा कि विपक्ष बार-बार चुनावी हार के बाद लोकतांत्रिक जनாदेश को चुनौती दे रहा है और अशांति फैलाने के लिए संविधान का बहाना बना रहा है।

नितिन नबिन ने कहा कि जब लोगों ने आपको नकार दिया और लोकतंत्र ने आपके खिलाफ फूसला सुनाया, तो उस फूसले को स्वीकार करने और उससे सीखने के बजाय, आपने देश को अस्थिर करने का मन बना लिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये कोशिशें विपक्ष के राजनीतिक मकसदों और विदेशी ताकतों के असर में की जा रही हैं। बीजेपी नेता ने यह भी चेतावनी दी कि देश में तनाव पैदा करने की इन कोशिशों का पार्टी और सरकार कड़ाई से जवाब देगी।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा, राहुल गांधी जो कर रहे हैं, भारत का युवा उन्हें देख रहा है। आप इस देश के सांविधानिक ढांचे को चुनौती दे रहे हैं और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका जवाब जनता देगी। जिन विदेशी ताकतों के दम पर आप राजनीति कर रहे हैं और भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके ये मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। नितिन नवीन ने कहा कि मैं चेतावनी देता हूं कि भाजपा और जनता, दोनों आपको जवाब देंगे। भारत सरकार कड़ाई से निपटेगी और आपके मंसूबों को रोकेगी। हम देश के प्रति प्रतिबद्ध हैं। विकसित भारत के सपने को



आगे बढ़ाएंगे और देशविरोधी ताकतों से सख्ती से निपटेंगे। सीजेपी को भी भारत का युवा देख रहा है। आम आदमी पार्टी समर्थित सीजेपी देश में अशांति फैलाने की कोशिश कर रही है।

उन्होंने कांग्रेस नेता पर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। नितिन नवीन ने कहा कि अलग-अलग राज्यों में विपक्ष की लगातार चुनावी हार उनकी हताशा को दिखाती है और आरोप लगाया कि अर्बन नक्सल सीच वाले कुछ समूह भारत की प्रगति में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं [नितिन नवीन ने कहा कि दुनिया भर में चल रहे संकटों के बावजूद भारत विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने आतंकवाद और नक्सलवाद से निपटने के प्रयासों का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में, हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, हमने देश को डर के माहौल से मुक्त करने, आतंकवाद को जड़ से खत्म करने और नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि भारत के अंदर और बाहर काम करने वाली ताकतें सरकार के विकास के एजेंडे में बाधा डालने की कोशिश कर रही हैं और चेतावनी दी कि ऐसी कोशिशों का कड़ा जवाब दिया जाएगा।

### विदेशी ताकतों से मिलकर अराजकता फैला रहा विपक्ष : शिवराज सिंह

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 10 अक्टूबर को नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (एनडीए) की हालिया उपचुनाव जीतों की तारीफ की। उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाया कि चुनाव में हारने के बाद वे लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए विदेशी ताकतों के साथ मिलकर साजिश रच रही हैं। चौहान ने कहा कि वोटरों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन के लिए अपना समर्थन फिर से जताया है। उन्होंने कहा कि कल हुए उपचुनावों में, चाहे बंगाल हो, असम हो या पुडुचेरी, भाजपा और एनडीए ने शानदार जीत हासिल की। जनता का फूसला साफ़ है- लोग कह रहे हैं कि हमारा संकल्प एक विकसित भारत बनाना है और हम इसे पूरा करेंगे। हम इसे हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और ऐसा करते रहेंगे।

उन्होंने विपक्षी पार्टियों की आलोचना करते हुए कहा कि वे लगातार संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ़, जनता विकास और विकसित भारत के निर्माण के लिए पीएम मोदी के साथ खड़ी है; दूसरी तरफ़, विपक्ष निराश और हताश है। वे चुनावी मैदान में जीत नहीं सकते और न ही जनता का भरोसा जीत सकते हैं। नतीजतन, वे सड़कों पर अराजकता फैलाने, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने, लोकतंत्र में विश्वास को खत्म करने की साजिश रचने और संविधान को तार-तार करने की कोशिश कर रहे हैं। चौहान ने आगे आरोप लगाया कि विपक्ष यह सब अकेले नहीं कर रहा है; वे विदेशी ताकतों के समर्थन से ऐसा कर रहे हैं। हालाँकि, जनता ने अपना रुख़ साफ़ कर दिया है- हम विकास और पीएम मोदी के साथ हैं। दिल्ली में चल रहे विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया देते हुए, चौहान ने इसे देश को अस्थिर करने की एक सोची-समझी चाल बताया।



### स्टेल प्रमुख समाचार

### किसी भी हार को हल्के में नहीं लेते : गौतम गंभीर



**नई दिल्ली।** भारतीय क्रिकेट टीम को शुक्रवार को रांची में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में 249 रन का विशाल स्कोर बनाने के बावजूद 6 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा। इस अप्रत्याशित हार के बाद भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने मीडिया से बात करते हुए बल्ले और गेंद के बीच अधिक कानूनी और संतुलित मुकाबले की आवश्यकता पर जोर दिया। गंभीर ने अपनी निराशा व्यक्त करते हुए युवा तेज गेंदबाज मयंक यादव के प्रदर्शन की जमकर तारीफ भी की। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर ने स्पष्ट शब्दों में कहा, आप किसी भी हार को हल्के में नहीं लेते। अगर आप सुधार करते रहना चाहते हैं, तो आप किसी भी बात को छिपाना नहीं चाहते। हम एक वर्ल्ड चैंपियन टीम हैं, इसलिए हम सुधार करते रहना चाहते हैं।

गंभीर ने स्वीकार किया कि गेंदबाजों के लिए हालात बेहद मुश्किल थे। उन्होंने कहा, ये साफ तौर पर गेंदबाजी के लिए मुश्किल हालात हैं। हम जानते हैं कि ओस वाली सपाट विकेटें होती हैं। यह मुश्किल है। हमें इसका हल निकालना होगा। उन्होंने वेस्टइंडीज को जीत का श्रेय दिया, विशेष रूप से शाई होप और शेरफेन रदरफोर्ड की बल्लेबाजी को। गंभीर ने कहा, वेस्टइंडीज को जीत का श्रेय जाता है। वेस्टइंडीज ने पहले ओवर में दो विकेट और फिर पावरप्ले में तीन विकेट गंवा दिए। इसके बाद शाई होप और शेरफेन ने शानदार बल्लेबाजी की। दोनों वर्ल्ड-क्लास बल्लेबाज हैं। यह हमारे लिए मुश्किल था, लेकिन हम सुधार करते रहेंगे। गंभीर ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए क्रिकेट की प्रकृति पर सवाल उठाया, जहाँ गेंदबाजों को अक्सर बल्लेबाजों के रहमोकरम पर छोड़ दिया जाता है। उन्होंने कहा, हालात ऐसे होने चाहिए कि बॉलर्स को बैटर्स के रहमोकरम पर छोड़ने के बजाय मुकाबला करने का सही मौका मिले।

### आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/

### प्रमुख समाचार

### आरबीआई तेल कंपनियों के लिए विशेष डॉलर सुविधा शुरू करेगा

**मुंबई।** भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शनिवार को कहा कि वह सार्वजनिक क्षेत्र की तीन तेल विपणन कंपनियों (ओएएससी) की संपूर्ण दैनिक डॉलर जरूरतों को पूरा करने के लिए सोमवार से एक विशेष सुविधा शुरू करेगा। केंद्रीय बैंक ने विदेशी मुद्रा बाजार में अनुशासन को मजबूत करने, उचित जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित करने और एक व्यवस्थित एवं पारदर्शी बाजार परिवेश बनाए रखने के लिए कई नियामकीय उपायों की भी घोषणा की। यह कदम ऐसे समय उठाया गया, जब लगातार भू-राजनीतिक और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच रुपए में गिरावट का खूब जारी है। आरबीआई ने जिन तीन तेल विपणन कंपनियों के लिए इस विशेष विंडी की घोषणा की है, वे हैं- इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि., हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

### केनरा एचएसबीसी लाइफ का लाभ दूसरी तिमाही में 5% बढ़ा

**नई दिल्ली।** केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का चौलू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में शुद्ध लाभ पांच प्रतिशत बढ़कर 43 करोड़ रुपए रहा।

बीमा कंपनी ने पिछले वित्तवर्ष की समान तिमाही में 41 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा अर्जित किया था। कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि केनरा बैंक प्रवर्तित बीमा कंपनी की कुल आय आलोच्य तिमाही में बढ़कर 2,511 करोड़ रुपए रही, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 2,349 करोड़ रुपए थी। कंपनी ने जुलाई-सितंबर तिमाही में 2,553 करोड़ रुपए का शुद्ध प्रीमियम जुटाया, जबकि पिछले वित्तवर्ष की समान तिमाही में यह 2,260 करोड़ रुपए था।

### इवेको के अधिग्रहण के लिए टाटा मोटर्स ने पेशकश मूल्य बढ़ाया

**नई दिल्ली।** टाटा मोटर्स लिमिटेड ने इटली की ट्रक विनिर्माता कंपनी इवेको ग्रुप एनवी के अधिग्रहण के लिए पेशकश मूल्य 0.30 यूरो बढ़ाकर 14.40 यूरो प्रति शेयर कर दिया है। कंपनी ने यह कदम नियामकीय मंजूरियों में देरी के मद्देनजर उठाया है। टाटा मोटर्स ने 2025 में अपनी अनुषंगी कंपनी टीएमएल सीवी होल्डिंग्स पीटीई लिमिटेड के माध्यम से इवेको के रक्षा कारोबार को छोड़कर उसके अन्य कारोबार के अधिग्रहण की योजना की घोषणा की थी। इस सौदे का मूल्य 3.8 अरब यूरो (करीब 38,240 करोड़ रुपए) आंका गया था। वाणिज्यिक वाहन क्षेत्र की प्रमुख कंपनी ने इससे पहले इवेको के लिए 14.10 यूरो प्रति शेयर की पेशकश की थी। इस आधार पर सौदे का मूल्य 3.82 अरब यूरो था। टाटा मोटर्स ने सितंबर में इवेको के सभी बकाया साधारण शेयरों के अधिग्रहण के लिए नकद भुगतान वाली स्वीच्छिक निविदा पेशकश शुरू की थी।

# विकसित भारत की राह में बड़ी चुनौतियां

अधिकारियों, कारोबार जगत से जुड़े वैश्विक दिग्गजों और शोध संस्थानों की हाल की बातों को ध्यान से सुनें तो भारत की तेज आर्थिक वृद्धि की तस्वीर उतनी आसान नहीं दिखती। इसके साथ कई शर्तें, चेतावनियां और व्यावहारिक चुनौतियां जुड़ी हुई हैं। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के मौजूदा शानदार आंकड़ों, भारत की संभावनाओं और उपलब्धियों की सामान्य तारीफ को एक तरफ रख दें तब इन बातों का सार यही मिलता है कि भारत को उन पुरानी और जानी-पहचानी आर्थिक कमियों से सावधान रहना होगा, जो उसकी तेज आर्थिक वृद्धि की यात्रा में बार-बार बाधा बनती रही हैं।

हाल ही में मुंबई में हुए 13वें एसबीआई बैंकिंग एंड इकॉनॉमिक कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव और देश के ताकतवर अफसरशाहों में से एक, पी. के. मिश्रा ने भारत की वैश्विक विनिर्माण



प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, आयात पर निर्भरता कम करने और युवाओं को बेहतर कौशल देने की जरूरत पर जोर दिया। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के मामले में उन्होंने बेहद स्पष्ट बात कही। उन्होंने कहा, 'इसके लिए कर नीतियों में स्थिरता जरूरी है। राज्यों द्वारा किए जाने वाले अनुबंधों में भरोसा होना चाहिए, लॉजिस्टिक्स व्यवस्था विश्वसनीय होनी चाहिए और सरकारी मंजूरियां वास्तव में समय पर मिलनी चाहिए।' उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इन चुनौतियों से पूरी तरह अवगत है और उन पर काम कर रही है।

उनकी इन टिप्पणियों से यह भी संकेत मिलता है कि विकसित देशों की श्रेणी में पहुंचने के लिए भारत को अभी लंबा रास्ता तय करना है।

इसी सम्मेलन में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी. अनंत नागेश्वरन ने भी मिश्रा की तरह ही कई महत्वपूर्ण चुनौतियों की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की रियायती विदेशी मुद्रा स्वेप सुविधा का जिक्र किया जिसके जरिए करीब 144 अरब डॉलर जुटाए गए हैं। उन्होंने इसे आरबीआई और सरकार की दूरदर्शिता का उदाहरण बताया और कहा कि इससे निकट भविष्य में भारत को काफी राहत मिलेगी। हालांकि उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि यह कोई स्थायी समाधान नहीं है।

सीईए के मुताबिक भारत को वैश्विक पूंजी आकर्षित करने के लिए आक्रामक

प्रतिस्पर्धा करनी होगी और इसके लिए केवल केंद्र सरकार की नीतियां पर्याप्त नहीं होंगी बल्कि राज्यों की नीतियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि निश्चित कर व्यवस्था और उसमें सरलता, निवेशकों की सुरक्षा, अनुसंधनों की विश्वसनीयता और निरंतरता तथा कुशल श्रमबल जैसे मुद्दों पर गंभीरता से काम करना होगा।

युवा आबादी को जनसांख्यिकीय लाभ के रूप में देखने के मामले में नागेश्वरन ने इसके बेहतर तरीके से प्रबंधन करने की बात कही। उनके अनुसार इस लाभ को केवल आबादी के आधार पर हासिल नहीं किया जा सकता। इसे सही तरीके से संभालना और हासिल करना होगा और इसके लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, दोनों को अपने काम करने के पुराने तरीकों में बदलाव और नए प्रयोग के लिए तैयार रहना होगा।

सैंध लेक सिटी और इलेशियम क्लब्स की साझेदारी घोषणा एवं अनुबंध हस्ताक्षर समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री

# विश्वस्तरीय खेल सुविधाओं से तैयार होंगे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी : साय

रायपुर। छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। आवश्यकता इन प्रतिभाओं को पहचानने, तराशने और उन्हें विश्वस्तरीय प्रशिक्षण एवं आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की है। राज्य सरकार इसी दिशा में योजनाबद्ध रूप से आगे बढ़ रही है। हमारा लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रदेश और देश का गौरव बढ़ाएं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर के जोरा में आयोजित सैंध लेक सिटी और इलेशियम क्लब्स की साझेदारी घोषणा एवं अनुबंध हस्ताक्षर समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर में प्रस्तावित विश्वस्तरीय स्पोर्ट्स क्लब की पहल का स्वागत करते हुए कहा कि इससे प्रदेश में खेल संस्कृति को नई मजबूती मिलेगी और युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण एवं खेल सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर क्लब के



संस्थापकों और पूरी टीम को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी एवं प्रशिक्षक श्री पुलेला गोपीचंद का छत्तीसगढ़ में स्वागत करते हुए कहा कि भारतीय बैडमिंटन को विश्व पटल पर नई पहचान दिलाने में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। उनके मार्गदर्शन में अनेक खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का गौरव बढ़ाया है। नवा रायपुर में उनकी

बैडमिंटन अकादमी की शुरुआत प्रदेश के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए बड़ी उपलब्धि साबित होगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि खेल केवल पदक जीतने का माध्यम नहीं है, बल्कि वे अनुशासन, आत्मविश्वास, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता का निर्माण भी करते हैं। खेलों में निवेश वास्तव में हमारी खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का गौरव बढ़ाया है। नवा रायपुर में उनकी

## बस्तर ओलंपिक ने बढ़ती तस्वीर

मुख्यमंत्री श्री साय ने बस्तर ओलंपिक का उल्लेख करते हुए कहा कि यह आयोजन दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों में छिपी खेल प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर देने का सशक्त मंच बना है। बस्तर ओलंपिक के पहले वर्ष में लगभग एक लाख 65 हजार खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। दूसरे वर्ष यह संख्या बढ़कर लगभग तीन लाख 91 हजार हो गई। खिलाड़ियों की बढ़ती भागीदारी बताती है कि बस्तर के युवाओं में खेलों को लेकर अभूतपूर्व उत्साह है और क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन की नई धारा प्रवाहित हो रही है। उन्होंने कहा कि बस्तर में आज युवा बंदूक और हिसा से दूर होकर खेल, शिक्षा, कौशल और रोजगार के माध्यम से अपने भविष्य को संवारने के लिए आगे आ रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि सुदूर गांव की प्रतिभा को भी वही अवसर और संघ मिले, जो बड़े शहरों के खिलाड़ियों को उपलब्ध हैं।

# शिविरों में मिल रहा योजनाओं का लाभ व समस्याओं का समाधान : लखनलाल

कोरबा। शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ नागरिकों तक पहुंचाने और उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत ‘सेवा हेतु अभियान सरकार आपके द्वार’ शिविर का आयोजन बालको जौन कार्यालय परिसर में किया गया। प्रदेश के वाणिज्य, उद्योग, श्रम, आबकारी एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन की अध्यक्षता में आयोजित शिविर में विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर नागरिकों को योजनाओं की जानकारी दी तथा उनकी समस्याएं सुनीं।

उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि केंद्र और राज्य शासन के निर्देशानुसार सेवा संकल्प अभियान के तहत विभिन्न क्षेत्रों में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य नागरिकों को शासकीय योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के साथ उनकी समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण करना है। शिविरों के माध्यम से लोगों को अपनी



समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार शासकीय कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिल रही है और शासन सीधे नागरिकों के बीच पहुंचकर उनकी जरूरतों को समझ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं से लोगों को खाद्यान्न, आवास, आर्थिक सहायता तथा बेहतर जीवन की सुविधाएं मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत

रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क को बढ़ावा मिला।

मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान खरीदी, तेंदूपत्ता का 5500 रुपये प्रति मानक बोरा संग्रहण पारिश्रमिक तथा महतारी वंदन योजना के माध्यम से पात्र महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपये की सहायता जैसी पहलें संचालित हैं।

# सरकार प्रदेश के प्रत्येक नगर और गांव के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध : टंकराम

बलौदाबाजार, सिमगा और तिल्दा-नेवरा विकासखंड को मिली करीब 5 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात



रायपुर। सरकार द्वारा प्रदेश के प्रत्येक नगर और गाँव के सर्वांगीण विकास तथा बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक और ऐतिहासिक पहल की गई है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री टंक राम वर्मा के विशेष प्रयासों से बलौदाबाजार विधानसभा को बुनियादी सुविधाओं, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर तथा शैक्षणिक ढाँचे को नई मजबूती प्रदान करने के लिए लगभग पौने

पांच करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी गई है। इस निर्णय से क्षेत्र के ग्रामीणों, व्यापारियों और विद्यार्थियों के बीच भारी उत्साह की लहर दौड़ गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों के चहुँमुखी विकास, शिक्षा के स्तर को सुधारने और मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए पूरी सरकार

तरह संकल्पित है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन विकास कार्यों के धरातल पर उतरने से ग्रामीण अंचलों में नागरिकों को आधुनिक एवं बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, जिससे बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में सुगमता होगी और विभिन्न सार्वजनिक आयोजनों व आवश्यकताओं के लिए मजबूत बुनियादी ढाँचा तैयार हो सकेगा।

वर्ष 2026-27 के लिए बलौदाबाजार और सिमगा विकासखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु 2 करोड़ 15 लाख 24 हजार रुपये की अनुमानित लागत से 42 नए विकास कार्यों को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

## कार्टून फेस्टीवल 13 को रायपुर में

रायपुर। देश की एकमात्र कार्टून पत्रिका कार्टून वॉच अपने 31वें वर्ष में प्रवेश करने वाली है और इस अवसर पर हर साल की तरह राजधानी रायपुर में कार्टून फेस्टीवल आयोजित किया जा रहा है। कार्टून वॉच के सम्पादक त्रयम्बक शर्मा ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि यह आयोजन 13 अक्टूबर को रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित होगा और इसके मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय होंगे। उल्लेखनीय है कि कार्टून फेस्टीवल में मुख्य अतिथि स्वयं सांकेतिक कार्टून बनाकर कार्यक्रम का उद्घाटन करते हैं। इस आयोजन की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह करेंगे और विशेष अतिथि के रूप में अनेक राजनीतिक हस्तियां मौजूद रहेंगी।

# मोदी देश की जनता का भरोसा खो चुके इस्तीफा दे : बैज



रायपुर। देश वोट चोरी के खिलाफ आक्रोशित है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि देश के युवाओं, छात्रों और आम नागरिकों का गुस्सा राजधानी दिल्ली की सड़कों पर दिख रहा था। मोदी सरकार के तमाम अवरोधों के बावजूद लाखों लोग मोदी और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सड़कों पर उतरे, यह बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी देश की जनता का भरोसा खो चुके हैं। उन्हें तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। पूरा देश भाजपा और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ गठबंधन से नाराज है। एसआईआर के नाम पर मोदी शाह के इशारे पर ज्ञानेश कुमार ने देश के 13 करोड़ सड़कें अधिक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से षड़यंत्रपूर्वक

के ही युवाओं से डरे हुए हैं। उसके बावजूद लाखों प्रदर्शनकारी राजधानी दिल्ली में पहुंचे हैं। देश के लोकतंत्र को बचाने का यह महान यज्ञ अब वोट चोर ज्ञानेश कुमार, वोट चोरी से प्रधानमंत्री बने मोदी के इस्तीफे के साथ ही यह आंदोलन खत्म होगा। राहुल गांधी की ओर पूरा देश आशा भरी निगाह से देख रहा, राहुल गांधी देश की आवाज बन चुके हैं।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन से घबराई मोदी सरकार ने पूरी दिल्ली को किले में तब्दील कर दिया है। दिल्ली की तरफ आने वाली ट्रेनों, बसों को रोक दिया गया। एन्बुलेंस को रोककर चेक किया गया। यह बताता है मोदी सरकार अपने देश

जवाब तथ्यों और निष्पक्ष जाँच से देने के बजाय सरकार लाठीचार्ज के पीछे क्यों छिप रही है ? जो सरकार जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकती, उसे सत्ता में बने रहने का क्या नैतिक अधिकार है ? देश के गद्दार और लोकतंत्र के आरोपी ज्ञानेश कुमार को बचाने भाजपा सरकार निर्ममता पूर्वक बर्बरता पर उतर आई है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि कांग्रेस की सोच और नीति सदैव जन-आंदोलनों को सुनने, संवाद कायम करने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने की रही है। राहुल गांधी सड़क से लेकर संसद तक देशवासियों के संवैधानिक अधिकारों के लिए निर्भीक होकर लड़ रहे हैं।

# छत्तीसगढ़/राजधानी प्रमुख समाचार

## मासूम से दुष्कर्म, बाल संरक्षण आयोग ने लिया संज्ञान

रायपुर। आमानाका थाना क्षेत्र में तीन साल की मासूम बच्ची के साथ कथित यौन अपराध के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने गंभीरता से संज्ञान लिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने मामले में आरोपी परमानंद ध्रुव को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा के संज्ञान में मामला आने के बाद आयोग ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए संबंधित अधिकारियों को तलब कर मामले की तथ्यात्मक जानकारी मांगी है। आयोग द्वारा मामले में की गई कार्रवाई, पुलिस जांच की स्थिति और पीड़ित बच्ची को उपलब्ध कराई जा रही सहायता के संबंध में जानकारी ली जा रही है। मामले में पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 3 एवं 4 सहित धारा 75 बच्चों के प्रति क्रूरता और बाल शोषण के तहत कार्रवाई की स्थिति की भी समीक्षा की जा रही है। आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है कि मामलों की जांच निष्पक्ष एवं प्रभावी ढंग से हो और पीड़ित बच्ची के अधिकारों की रक्षा के साथ उसे आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाए। आयोग ने स्पष्ट किया है कि बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।



## महिला मोर्चा का राजीव भवन घेराव स्तरहीन नौटंकी : कांग्रेस

रायपुर। भाजपा महिला मोर्चा के द्वारा कांग्रेस कार्यालय में किए गए प्रदर्शन को प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने महिला मोर्चा की स्तरहीन नौटंकी बताया है। मणिपुर में महिलाओं पर लंबे समय से अत्याचार हो रहा महिलाएं जिंदा जलाई जा रही उनके साथ सामूहिक दुराचार की घटनाएं लगातार हो रही तब महिला मार्चा को लकवा मार गया था। कभी महिला मोर्चा ने मणिपुर की महिलाओं की सुरक्षा, उनके जानमाल की रक्षा के लिए मोदी सरकार के सामने आवाज कभी क्यों नहीं उठाया ? महिला मोर्चा महिलाओं के संबंध में सेलेक्टिव पॉलिटिक्स बंद करे। प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि भाजपा महिला मोर्चा कांग्रेस ऑफिस का घेराव पर केवल मोदी सरकार के खिलाफ वोट चोरी को लेकर बने देश व्यापी माहौल से ध्यान भटकाने के लिए किया है। महिला मोर्चा प्रदेश में रोज हो रही महिला अत्याचार, राज्य में प्रतिदिन हो रहे 8 बलात्कार की घटनाओं के खिलाफ क्यों मौन है ? बालोद में मासूम छात्रा पर एसिड अटैक होता है महिला मोर्चा एक निंदा के बयान नहीं देती है। अब मणीपुर की घटना को लेकर कांग्रेस दफ्तर घेरने बेशर्मीपूर्वक आ गयी।



## जतमई धाम को प्लास्टिक मुक्त बनाने नागरिकों ने किया श्रमदान

गरियाबंद। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत ‘सेवा मेरा योगदान’ कार्यक्रम के तहत शनिवार को जतमई माता मंदिर परिसर में वृक्षारोपण एवं प्लास्टिक मुक्त स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया। गरियाबंद वनमंडल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में राजिम विधायक रोहित साहू, कलेक्टर रणबीर शर्मा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रखर चंद्राकर और वनमंडलाधिकारी मयंक पांडे सहित जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों ने सहभागिता निभाई। अतिथियों ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और हाथों में झाड़ू लेकर मंदिर परिसर के विभिन्न हिस्सों की सफाई की। सभी ने कचरा एकत्र कर धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाए रखने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान विधायक श्री रोहित साहू ने रुद्राक्ष का पौधा लगाया, जबकि कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा ने वटवृक्ष का पौधा रोपण किया। अन्य अतिथियों ने भी पौधरोपण कर हरित वातावरण विकसित करने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का संदेश दिया। पौधरोपण के बाद जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और नागरिकों ने हाथों में झाड़ू लेकर मंदिर परिसर के विभिन्न हिस्सों में सफाई की। इस दौरान कचरे को एकत्र किया गया और लोगों को स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया।



## टी 20 मैच की तैयारियों को लेकर कलेक्टर ने ली बैठक

रायपुर। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने 16, 18 एवं 20 अक्टूबर को राजधानी के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होने वाले इंडिया 1व्हा जिम्बाब्वे टी 20 मैच की तैयारियों को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ के साथ बैठक लकलेक्टर डॉ. सिंह ने कहा कि यह छत्तीसगढ़ के लिए महत्वपूर्ण आयोजन है। पार्किंग की मयंक पांडे सहित स म्ु फ च त व्यवस्था की जाए तथा सामानों की ओवररैटिंग न हो। पुलिस प्रशासन से समन्वय कर सुरक्षा एवं ट्रैफिक के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। उन्होंने कहा कि मैदान में खिलाड़ियों के साथ दर्शकों के लिए आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित रहें। प्रशासन की एसओपी का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए। आपदा के समय क्या किया जाए, इसकी कार्ययोजना पहले से तैयार रखें। डॉ. सिंह ने कहा कि अगर से बचाव के लिए आवश्यक उपकरणों का अनिवार्य रूप से इंतजाम किया जाए तथा जिला सेनानी से समन्वय स्थापित कर उपकरणों का पूर्व परीक्षण कर लिया जाए। सभी दर्शकों की सुविधाजनक आवाजाही सुनिश्चित की जाए और मैडिकल सुविधा का अनिवार्य रूप से इंतजाम किया जाए।



## भाजपा सरकार में खराब सड़के छग की पहचान बन गई : कांग्रेस

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने प्रदेश की बदहाल सड़कों को लेकर कहा कि उपमुख्यमंत्री एवं लोकनिर्माण मंत्री अरुण साव सड़कों की मरम्मत कराने में असफल हो गये हैं। नयी सड़क बनाना तो दूर की बात पुरानी सड़कों की मरम्मत भी नहीं कर पा रहे हैं। प्रदेश के 10 हजार किलोमीटर से अधिक सड़क चलने लायक नहीं हैं। जिसका खामियाजा आम जनता वाहन मालिक भुगत रहे हैं। भाजपा सरकार में खराब सड़के छत्तीसगढ़ की पहचान बन गई है। भाजपा सरकार के विकास के दावे की पोल सड़कों के गड्ढे, उड़ती हुई धूल, खराब होती गाड़ियां खोल रही हैं। खराब सड़के आम जनता के लिए परेशानी और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ा रही है। सरकार की जवाबदेही कहीं दिखाई नहीं देती। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय सड़क निर्माण, आवागमन और बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने के दिशा में बेहतर काम हुआ था। आज भाजपा सरकार के सामने उन सुविधाओं को बेहतर बनाए रखने की चुनौती है। भाजपा ने सुशासन और विकास के नाम पर जनता से बड़े-बड़े दावे किए थे, लेकिन बदहाल सड़कों ने इन दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।



# मुख्य सचिव की अध्यक्षता में डिजिटल क्राँप सर्वे की प्रगति की समीक्षा बैठक सम्पन्न

# डिजिटल क्राँप सर्वे का शेष कार्य 10 नवम्बर तक पूरा करें : विकासशील

रायपुर। मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में डिजिटल क्राँप सर्वे (डीसीएस) की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी जिलों के कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। बैठक में डिजिटल क्राँप सर्वे की प्रगति, खसरों की जियो-रेफरेंसिंग, पॉलीगॉन निर्माण, फसल की वास्तविक स्थिति के सत्यापन तथा सर्वे के डेटा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई।

राजस्व सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी ने बताया कि राज्य में अब तक 93.84 प्रतिशत डिजिटल क्राँप सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है। मुख्य सचिव ने शेष कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि डिजिटल क्राँप सर्वे का उद्देश्य



प्रत्येक खसरे में बोई गई फसल के क्षेत्रफल को वास्तविक स्थिति के आधार पर दर्ज करना है। इसके लिए फसल का भौतिक सत्यापन, जियो-टैगिंग, पॉलीगॉन निर्माण तथा संबंधित जानकारी को डिजिटल क्राँप सर्वे में दर्ज कर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाए।

10 नवंबर तक पूरा करें सर्वे का शेष

कार्य

मुख्य सचिव ने अधिकारियों और कलेक्टरों को निर्देश दिए कि डिजिटल क्राँप सर्वे का शेष कार्य हर हाल में 10 नवंबर तक पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन खसरों का नक्शा उपलब्ध नहीं है या जिनकी जियो-रेफरेंसिंग नहीं हुई है, उनकी पहचान कर पॉलीगॉन तैयार किए जाएं और फसल

संबंधी जानकारी डिजिटल क्राँप सर्वे में दर्ज कर अपलोड की जाए। इसके लिए जिलों में उपलब्ध ग्रामवार डेटा का उपयोग करते हुए शेष खसरों में धान अथवा अन्य फसलों की वास्तविक स्थिति दर्ज की जाए। पिछले वर्ष के फसल संबंधी रिकॉर्ड का भी आवश्यकतानुसार संदर्भ लिया जाए।

उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में सर्वे का कार्य 90 प्रतिशत या उससे अधिक पूरा हो चुका है, वहां शेष कार्यों को तेजी से पूरा करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाएं। सर्वेयर, पटवारी और राजस्व विभाग के अन्य मैदानी अमले को सक्रिय कर ग्रामवार प्रगति की नियमित समीक्षा की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सर्वे का कार्य केवल औपचारिकता के लिए नहीं, बल्कि वास्तविक फसल स्थिति के आधार पर पूरा होना चाहिए।

# दीपावली से पहले शहर को कचरामुक्त करें, सेवाओं में देरी बर्दाश्त नहीं : सोनमणि

रायपुर। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने भिलाई नगर निगम के अधिकारियों को नागरिकों को समय पर सेवाएं देने और शिकायतों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नागरिक कष्टमर हैं, इसलिए सेवाओं में देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को रोज सुबह फील्ड निरीक्षण करने और दीपावली से पहले शहर को कचरामुक्त बनाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने 15वें वित्त आयोग के तहत चल रहे अधूरे निर्माण कार्यों की धीमी गति पर नाराजगी जताई।

प्रमुख सचिव श्री बोरा ने नवा



रायपुर स्थित सर्किट हाउस में आयोजित समीक्षा बैठक में भिलाई नगर निगम में लॉबत कार्यों और नागरिक सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कार्यप्रणाली में सुधार लाने और नागरिकों के प्रति संवेदनशील व्यवहार करने को कहा। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संचालक श्री नीलेश क्षीरसागर, सूडा के सीईओ श्री सुमीत

अग्रवाल और भिलाई नगर निगम की आयुक्त सुशी सुर्चि सिंह भी बैठक में मौजूद थीं। प्रमुख सचिव ने जोन कमिश्नरों, उपायुक्तों और अपर आयुक्तों को प्रतिदिन सुबह मॉनिंग विजिट करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी अपने क्षेत्रों की व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर कमियां और कार्यों की प्रगति की रिपोर्ट निर्धारित रूप में साझा करें।